घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 198- बुधवार 20 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पीएम मोदी इंडिया-नॉर्डिक समिट में शामिल हुए....डेनमार्क-आइसलैंड,फिनलैंड के पीएम से मिले,स्ट्रैटेजिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर

भारत और नॉर्डिक संबंधों में स्वर्णिम युग का आगाज : पीएम मोदी

ओस्लो,19 मई 2026। मोदी ने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून का सम्मान के नरजिए से भारत और नॉर्डिक देशों को स्वाभाविक साझेदार हैं। नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन शामिल हैं। पीएम ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में यह साझेदारी और आगे बढ़ेगी। इससे पहले मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्टेरी ओर्पो और आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुन म्योल फ्रॉस्टाडोटिर से भी मुलाकात की। इस समिट का मकसद भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करना था। प्रधानमंत्री मोदी इस समय पांच देशों के दौरे पर हैं। नॉर्वे उनका चौथा पड़ाव है। इससे पहले वह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं।

आतंकवाद पर बोले पीएम मोदी-हमारा रुख साफ,कोई समझौता नहीं,कोई दोहरा मापदंड नहीं

ओस्लो में तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मुद्दों पर भारत और नॉर्डिक देशों के साझा और स्पष्ट दृष्टिकोण को सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज के वैश्विक तनाव और संघर्ष के दौर में भारत और नॉर्डिक देश मिलकर एक 'नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था'पर जोर देते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया,दोनों पक्ष जल्द से जल्द युद्धविराम और शांति प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख बिल्कुल साफ और संयुक्त है, 'नो कॉम्प्रोमाइज,नो डबल स्टैंडर्ड्स' यानी कोई समझौता नहीं,कोई दोहरा मापदंड नहीं।

भारत और नॉर्डिक देशों के बीच संबंधों के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए,हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की हैं। अक्टूबर 2025 से,हमने नॉर्वे,आइसलैंड और अन्य यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को प्रभावी बनाया है। अभी कुछ महीने पहले ही, हमने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डेनमार्क,फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। इस महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के साथ,हम भारत और नॉर्डिक देशों के बीच संबंधों के लिए एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।

पीएम मोदी बोले- ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए बनेगा वैश्विक समाधानों का नया रोडमैप

तीसरे भारत–नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को 'ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' का नया रूप देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साझेदारी के तहत नॉर्डिक देशों की अनूठी विशेषज्ञता को भारत के कौशल और प्रतिभा के साथ जोड़ा जाएगा। इसके जरिए आइसलैंड की जियोथर्मल व मत्स्य पालन,नॉर्वे की ब्लू इकॉनमी व आर्कटिक विशेषज्ञता, और सभी नॉर्डिक देशों की समुद्री व सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञता का लाभ भारत को मिलेगा। साथ ही, स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग व रक्षा क्षेत्र, फिनलैंड की टेलीकॉम व डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सुरक्षा व हेल्थ टेक को भारतीय प्रतिभा से जोड़कर पूरी दुनिया के लिए भरोसेमंद समाधान विकसित किए जाएंगे,जिससे वैश्विक स्तर पर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके।

आर्थिक तूफान आने वाला है....बहुत कठिन समय आ रहा है एक्शन लेने के बजाए मोदीजी विदेश चले गए : राहुल गांधी

रायबरेली,19 मई 2026। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दो दिन के यूपी दौरे पर हैं। मंगलवार को रायबरेली में उन्होंने कहा- अब आर्थिक तूफान आने वाला है। पीएम मोदी ने अदाणी और अंबानी वाला जो आर्थिक ढांचा बनाया है, वह टूटकर गिरेगा। इसका नुकसान आम जनता को होगा। यूपी की जनता को शॉक लगेगा। बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन की बजाए पीएम कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा- हम आपके साथ खड़े हैं। जहां भी आप जाएंगे, मुझे बुला लीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। आपने मेरा समर्थन किया, आपने बारात घर की मांग की थी, हमने आपको बारात घर भी दे दिया। अगली बार जब यहां शादी होगी तो मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं जरूर आऊंगा। हमारा रिश्ता प्यार का है, दिल का रिश्ता है, परिवार जैसा रिश्ता है। जनता मेरे लिए माता-पिता, दादी, बहन और भाई जैसी है। राहुल मंगलवार सुबह 11.30 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने उनका स्वागत किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक बैनर-पोस्टर लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने 'राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाए।

राहुल बोले...मोदी जी की राजनीति एक ही दिशा में रही नफरत फैलाना

राहुल गांधी ने खीरो में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा...आपने लोकसभा चुनाव में हमारा पूरा समर्थन किया। भारी बहुमत से हमें जिताया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपसे देश के हालात पर भी बात करना चाहता हूं। आज देश में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। पिछले 10 से 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी की राजनीति एक ही दिशा में रही है- नफरत फैलाना, लोगों का ध्यान भटकाना और जनता की संपत्ति, चाहे वह किसानों की हो, मजदूरों की हो, छोटे व्यापारियों की हो या युवाओं की। उसे कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में पहुंचाना। राहुल ने कहा...लोग पूछते हैं कि मजदूरों से धन कैसे छीना गया, तो मैं बताना चाहता हूं। हर साल मनरेगा जैसी योजनाओं के जरिए मजदूरों को रोजगार और पैसा मिलता था। करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलता था, लेकिन आरोप है कि इस व्यवस्था में बदलाव कर कई जगहों पर इसका असर कम हुआ।

राहुल बोले...देश को बदलना है तो मोदी जी आपको बात समझनी होगी : राहुल गांधी ने कहा- आज की स्थिति को हल्के में लिया जा रहा है। सरकार को मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुरंत एक्शन लेकर देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा करनी चाहिए। हम हर रोज पीएम मोदी से कह रहे हैं कि किसानों, व्यापारियों, मजदूरों की रक्षा करना शुरू करो। अगर आप नहीं करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अब अगर देश को बदलना है तो नरेंद्र मोदी जी आपको यह बात समझनी होगी। राहुल ने कहा...नरेंद्र मोदी कहते है कि सोना मत खरीदो,इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, विदेश मत जाओ। इतना कहने के बाद नरेंद्र मोदी विदेश चले जाते हैं। दुःख की बात है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है,जिसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है, जो आपने हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इसकी चोट किसको लगेगी। अंबानी-अदाणी अपने महलों में बैठे रहेंगे। उनके महलों में चारों ओर सिक्योरिटी होगी। हिंदुस्तान के मजदूर, युवाओं, छोटे व्यापारियों को चोट लगेगी।

नोटबंदी के दौरान भी आम जनता को कठिनाई हुई : राहुल

राहुल ने कहा... आरोप यह भी है कि बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया, जबकि आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर इसका विपरीत असर पड़ा। नोटबंदी के दौरान भी आम जनता को कठिनाई हुई। लोगों की बचत और नगद लेन-देन प्रभावित हुआ। यह राजनीति नफरत फैलाने, ध्यान भटकाने और जनता के संसाधनों के केंद्रीकरण की दिशा में रही है।

खतरनाक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को दिया जा सकता है मौत का इंजेक्शन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा- लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि, आदेश न मानने वाले अधिकारियों पर चले अवमानना का केस

नई दिल्ली,19 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा और खतरनाक कुत्तों से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि रेबीज संक्रमित या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को कानून के तहत इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आम लोगों की जान की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें वे आवेदन भी शामिल थे, जिनमें डॉग लवर्स और कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के पहले जारी निर्देशों को रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देशभर में बढ़ रही डॉग बाइट घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि अकेले राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महीने के भीतर कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आईं। कई छोटे बच्चों के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। कोर्ट ने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां साल 2026 के पहले चार महीनों में ही करीब दो लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकारों और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाने की बात कही गई थी।

इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करें। हर जिले में कम से कम एक पूर्ण रूप से कार्यरत एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार एबीसी सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन,प्रदेश में शोक की लहर

देहरादून,19 मई 2026। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का आज निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही उत्तराखंड समेत राष्ट्रीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। पिछले कई दिनों से उनके आवास पर नेताओं, समर्थकों और परिजनों का आना-जाना लगा हुआ था। पुष्कर सिंह धामी ने खंडूड़ी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेजर जनरल खंडूड़ी ने सेना और सार्वजनिक जीवन दोनों में अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण की मिसाल पेश की। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास और सुशासन में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। खंडूड़ी को राजनीति में लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाता है। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और जल्द ही भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। वर्ष 1999 में वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को नई गति दी। खंडूड़ी ने 2007 से 2009 और फिर 2011 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें साफ छवि, सादगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए जाना जाता था। उनका निधन राज्य और भाजपा के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है।

भारत में आईएसआई की ड्रोन के जरिए नकली नोट भेजने की साजिश,भारतीय एजेंसियां अलर्ट

नई दिल्ली,19 मई 2026। एजेंसियों की जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की आईएसआई और उसके मददगार भारत में बड़े पैमाने पर नकली नोट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता के इलाके त्रिपुरा-बांग्लादेश बॉर्डर और पंजाब हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोट भारत में पहुंचाने के लिए कूरियर का इस्तेमाल किया जा रहा है,जबकि पंजाब में ड्रोन के जरिए यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि नकली भारतीय नोटों को लेकर आईएसआई ने दो तरफा रणनीति अपनाई है। एक तरफ उसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है, और दूसरी तरफ वह पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के लिए फंड जुटाना चाहती है। अधिकारी ने कहा कि पंजाब की तुलना में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर यह समस्या ज्यादा गंभीर है। इस समस्या से निपटने में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) सबसे आगे काम कर रही है। एनआईए बॉर्डर पर इस खतरे को रोकने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के अंदर भी कई मामलों की जांच कर रही है। राज्य में उसका मुख्य फोकस मालदा पर है, जहां नकली नोट छापने वाली कई यूनिट्स सामने आई हैं।

आम आदमी पर महंगाई की डबल मार : पेट्रोल-डीजल फिर हुआ महंगा

तेल कंपनियों ने करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए दाम

नई दिल्ली,19 मई 2026। देश में महंगाई के बीच आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा किया गया है। पांच दिनों के भीतर ईंधन कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है, जिससे आम जनता की चिंता और बढ़ गई है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे लोगों की जेब पर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में सब्जियों, दूध, राशन और अन्य जरूरी सामानों के दाम भी बढ़ सकते हैं। नई कीमतों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

होर्मुज संकट का असर : सुजाता

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की वजह पश्चिम एशिया में जारी संकट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति को बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय तनाव को ढाई महीने से ज्यादा समय हो चुका है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, नेचुरल गैस और एलपीजी की कीमतों में लगातार उछाल बना हुआ है। सरकार के मुताबिक इसका असर भारत के क्रूड ऑयल, एलपीजी और नेचुरल गैस आयात पर भी पड़ा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं तथा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

राहुल ने पेट्रोल-डीजल के दाम और महंगाई पर सरकार को घेरा

राहुल ने कहा... पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई आसमान के ऊपर जा रही है। वह कहते हैं कि राहुल को कोई समझ नहीं है। हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए। लेकिन, उनको कुछ लेना देना नहीं है। कभी हवाई जहाज से नॉर्वे चले जाते हैं, कभी जापानी चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं।

वायु सेना को नए सौदे का पहला सुखोई-30 लड़ाकू विमान अगले साल देगा एचएएल

नई दिल्ली,19 मई 2026। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने भारतीय वायु सेना के लिए खरीदे गए एक दर्जन नए सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस नए सौदे का पहला जेट वित्त वर्ष 2027-28 के दौरान सौंपा जाएगा। बाकी ग्यारह विमान अगले साल वित्त वर्ष 2028-29 में वायु सेना के बेड़े में शामिल होंगे। इन विमानों की आपूर्ति होने पर वायु सेना की लड़ाकू क्षमता मजबूत होने के साथ ही हाल के दशकों में टूट-फूट और दुर्घटनाओं के कारण हुई विमानों की कमी पूरी हो सकेगी।

वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के लिए कंपनी की वित्तीय समीक्षा के दौरान एचएएल के अधिकारियों ने भारतीय वायु सेना के लिए किये गए सौदे के 12 सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के बारे में पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय ने 12 दिसंबर, 2024 को इन 12 ट्विन-इंजन, मल्टीरोल प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए एचएएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन विमानों और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए यह सौदा 13,500 करोड़ रुपये का है। इन विमानों में 62.6 फीसदी स्वदेशी सामग्री होगी और इनका निर्माण एचएएल के नासिक डिवीजन में किया जा रहा है। इन विमानों की आपूर्ति से भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और देश की रक्षा तैयारियां मजबूत होंगी।

जम्मू-कटरा रेलखंड पर ढलान को स्थिर करने और सुरंगों की मरम्मत को 238 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली,19 मई 2026। भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के जम्मू-श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलखंड पर ढलान को स्थिर करने, सुरंगों की मरम्मत और पुलों के सुरक्षा कार्यों के लिए 238 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस रेलखंड की दीर्घकालिक सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह देश के सबसे दुर्गम इलाकों में सुरक्षित और भरोसेमंद रेल संपर्क सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कटिंग, पुल और सुरंगों का विस्तृत आकलन करने के बाद सुरक्षा एवं पुनर्वास कार्यों को मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत ढलान को स्थिर करना, सुरंगों से पानी रिसने की समस्या का समाधान, पुलों के सुरक्षा कार्य तथा संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा से जुड़े अन्य उपाय शामिल हैं। रेलवे के अनुसार, इन कार्यों से जम्मू-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा रेलखंड की संरचनात्मक मजबूती और परिचालन सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह रेलखंड कठिन भूभाग, प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों और मौसम की चरम घटनाओं के कारण लंबे समय से इंजीनियरिंग और परिचालन चुनौतियों का सामना करता रहा है।

आबकारी घोटाला : केजरीवाल-सिसोदिया समेत आप नेताओं को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस,चार हफ्तों में मांगा जवाब

नई दिल्ली,19 मई 2026। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना (क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट) के एक स्वतः संज्ञान मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह सहित अन्य आप नेताओं को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति स्वराना कांता शर्मा द्वारा शुरू किए गए इस मामले में आरोप है कि शराब नीति मामले में न्यायमूर्ति शर्मा की अदालत से रिक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद 20 अप्रैल को आप नेताओं ने अदालत का बहिष्कार किया और सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो तथा पत्रों के माध्यम से उनके खिलाफ अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां कीं। दो-न्यायाधीशों न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने सभी आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। आप नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जो अदालत की गरिमा के विरुद्ध है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि वे आबकारी नीति मामले के कुछ बरी किए गए आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर उनके और अदालत के खिलाफ की गई अत्यंत अपमानजनक, मानहानिकारक और घृणित टिप्पणियों पर चुप नहीं रह सकती हैं।

देश के कृषि विकास का ग्रोथ का इंजन बन सकता पूर्वी भारत : शिवराज

भुवनेश्वर,19 मई 2026। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के पूर्वी राज्य की उर्वरा भूमि, जल की उपलब्धता, किसानों की मेहनत और परिश्रम, मिट्टी के विविध प्रकार और जलवायु सचमुच अद्भुत हैं। यदि सही दिशा में थोड़े और प्रयास किए जाएं, तो पूर्वी भारत देश के कृषि विकास का ग्रोथ का इंजन बन सकता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मंगलवार को 'पूर्वांचल क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन-2026' का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के पांच राज्यों के कृषि विकास एवं किसानों के कल्याण के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई।

संपादकीय

मुनाफे का जानलेवा खेल

इंसानी जीवन मूल्यों में किस हद तक गिरावट आई है कि कुछ लालची लोग मुनाफे के लिये दूसरे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते। अब चाहे सुकोमल व बीमारियों के संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील छोटे बच्चे ही क्यों न हों। निस्संदेह,जीवनदायिनी दूध में मिलावट,इंजेक्शन लगे फल-सब्जी तथा नकली दवाइयों का कारोबार जैसे घातक कृत्य से मुनाफा कमाने में लगे लोगों की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। कल्पना करें कोई बीमार व्यक्ति सेहत के लिये दूध का सेवन करे और उसे रासायनिक पदार्थों से मिला दूध मिले तो वह स्वस्थ होने के बजाय बीमार ही हो जाएगा। ऐसा ही नकली-मिलावटी दवाइयों के बाबत कहा जा सकता है कि कोई बीमारियों से मुक्त होने हेतु दवा खरीदे और उसे नकली दवाइयां बेच दी जाएं। लेकिन इससे भी घातक वह कुकृत्य है जिसमें पंजाब में बायोमेडिकल कचरे की अवैध रीसाइक्लिंग से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दुखद ही है कि अस्पतालों और ब्लड बैंकों से एकत्र खतरनाक बायोमेडिकल कचरे को निर्धारित नियमों को ताक में रखकर रीसाइक्लिंग के लिये भेजा जा रहा था। जबकि सख्त नियमों के अंतर्गत प्रावधान है कि बायोमेडिकल कचरे को अनिवार्य रूप से नष्ट किया जाना चाहिए। खबरें तो ऐसी भी आई हैं कि बायोमेडिकल कचरे से रिसाइकल किया गया प्लास्टिक,मेडिकल उपकरण,यहां तक कि सस्ते खिलौने बनाने वालों तक पहुंच रहा है। उल्लेखनीय है कि बायोमेडिकल कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के रूप में पाया जाता है,जो सस्ती उपलब्धता के कारण उत्पादकों की लागत कम कर देता है। वहीं कुछ उत्पादों को साफ करके फिर से बाजार में उतारने की भी आशंका है। दरअसल,जानलेवा अवैध कारोबार का खुलासा तब हुआ,जब पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक गोदाम से भारी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा बरामद किया। निश्चित ही,इस घातक खेल में ऐसे लोग भी शामिल होंगे,जो मेडिकल कचरे को नष्ट करने के बजाय चंद रुपयों के लिये उसे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।

निस्संदेह,इस जानलेवा खेल के पीछे एक सुनियोजित सांठगांठ वाले गिरोह की भूमिका होगी। जिसके जरिये बायोमेडिकल कचरे को गोदामों से निकालकर स्क्रैप डीलरों के माध्यम से बेचा गया। पुलिस के छापे में गोदाम से खून से सने कॉटन पैड,प्रयोग की गई सिरिंज और खून के सैंपल वाली बोतलों समेत कई ऐसे मेडिकल वेस्ट मिले हैं जो घातक संक्रमण फैलाने का जरिया बन सकते हैं। कुछ लालची लोग मुनाफे के लिये यह जानलेवा काम कर रहे हैं,लेकिन सवाल यह कि नियामक तंत्र की मौजूदगी में ये खेल कैसे चल रहा था? उल्लेखनीय है कि पंजाब में अमृतसर,लुधियाना,मुक्तसर,मोहली,नकोदर और पठानकोट में छह बोयोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सुविधाएं मौजूद हैं। इन सभी यूनिटों द्वारा हर दिन बीस हजार किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण किया जाता है। जिसकी निगरानी के लिये पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बारकोडिंग प्रणाली के जरिये जानकारी जुटाता है। इतना ही नहीं,कचरा ढोने वाले वाहनों की ट्रैकिंग और अन्य जानकारियां ऑनलाइन अपलोड की जाती हैं। सवाल यह उठता है कि इस अपवित्र कृत्य की कमजोर कड़ी कहां है? पुलिस सूत्रों ने इशारा किया है कि बायोमेडिकल कचरे पर मोहाली की एक अधिकृत कचरा संग्रहण कंपनी के बारकोड लगे थे। स्पष्ट है कि मानव स्वास्थ्य के लिये घातक कचरे को वैध निपटान प्रक्रिया से गुजारने के बजाय मुनाफे के लिये बाजार में बेच दिया गया। कहना कठिन है कि यह खतरनाक खेल कब से चल रहा था और न जाने कितने लोगों को घातक संक्रमण का शिकार बना दिया गया होगा। निस्संदेह,यदि प्रवर्तन एजेंसियां ईमानदारी से सख्त कार्रवाई करें तो अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। सूत्र बताते हैं कि इस प्रकरण में एक ऐसी कंपनी की कारगुजारी संदिग्ध है,जिसे बायोमेडिकल कचरे के अनुचित प्रबंधन मामले में पहले भी पकड़ा जा चुका है।

दवा के नाम पर मौत,इलाज के नाम पर भय कब तक?

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत,समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। आर्थिक प्रगति,डिजिटल क्रांति,आधारभूत ढांचे का विस्तार,तकनीकी उन्नयन और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा आशा जगाती है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती धांधलियां,फर्जी डॉक्टरों की नियुक्तियां,नकली दवाओं का कारोबार,अस्पतालों में मुनाफाखोरी और चिकित्सा सेवाओं का व्यवसायीकरण इस विकास यात्रा पर गहरे प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। यदि नागरिकों का जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो विकास के सारे दावे खोखले प्रतीत होंगे। मध्यप्रदेश के दमोह और जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में फर्जी डॉक्टरों की नियुक्तियों का खुलासा किसी एक राज्य की प्रशासनिक विफलता नहीं,बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरी का प्रतीक है। इससे भी अधिक चिंताजनक मामला राजस्थान मेडिकल काउंसिल में सामने आया,जहां ऐसे लोगों को डॉक्टर के रूप में पंजीकृत कर दिया गया जिन्होंने न मेडिकल शिक्षा प्राप्त की और न ही आवश्यक इंटर्नशिप की। यह केवल कागजी अनियमितता नहीं,बल्कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाला गंभीर अपराध है। एक अयोग्य व्यक्ति जब डॉक्टर बनकर मरीजों के सामने बैठता है,तब वह इलाज नहीं करता,बल्कि मानव जीवन पर प्रयोग करता है,उसके कारण जिंदगी मौत में बदल जाती है।

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सेना,अर्थव्यवस्था,तकनीकी उपलब्धियों या ऊंची इमारतों से नहीं मापी जाती,बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह अपने नागरिकों के जीवन,स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति कितना संवेदनशील है। स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी देश की आत्मा होती है। अस्पताल केवल भवन नहीं होते,वे जीवन की उम्मीद के केंद्र होते हैं। डॉक्टर केवल पेशेवर व्यक्ति नहीं होता,वह मौत और जीवन के बीच खड़ा वह संवेदनशील रक्षक होता है,जिस पर मनुष्य सबसे अधिक विश्वास करता है। लेकिन जब यही स्वास्थ्य व्यवस्था भ्रष्टाचार,फर्जीवाड़े, मुनाफाखोरी और अनैतिकता की गिरफ्त में आ जाए,तब समाज का विश्वास टूटने लगता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। आज भारत में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी जो घटनाएं सामने आ रही हैं,विशेषकर मध्यप्रदेश और राजस्थान की घटनाओं ने इसी भयावह यथार्थ को उजागर किया है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसे लोग व्यवस्था में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? क्या कोई व्यक्ति अकेले इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकता है? निश्चित रूप से नहीं। इसके पीछे सत्यापन तंत्र की विफलता,विभागीय मिलीभगत और संस्थागत भ्रष्टाचार की परतें मौजूद होती हैं। जब मेडिकल काउंसिल,अस्पताल प्रशासन और परीक्षा एवं पंजीयन संस्थाओं की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाए,तब यह स्पष्ट हो जाता है कि बीमारी केवल व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में फैल चुकी है। आज चिकित्सा क्षेत्र का संकट केवल फर्जी डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। निजी अस्पतालों में मुनाफाखोरी ने स्वास्थ्य सेवा के मानवीय स्वरूप को गंभीर क्षति पहुंचाई है। मरीज की विवशता को आर्थिक अवसर में बदल देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अनेक मामलों में अनावश्यक जांचें कराना, जरूरत न होने पर मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना,वेंटिलेटर पर रखना,अत्यधिक बिल बनाना और उपचार को लंबा खींचना आम शिकायतें बन चुकी हैं। मरीज अस्पताल में इलाज के लिए जाता है, लेकिन कई बार आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार होकर लौटता है। चिकित्सा सेवा का मूल उद्देश्य पीड़ा दूर करना था,लेकिन कई स्थानों पर वह व्यापार और लाभ कमाने का माध्यम बन गई है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए बने इन संस्थानों में संसाधनों की कमी,कर्मचारियों की लापरवाही,भ्रष्टाचार और बिचौलियों की दखलअंदाजी ने व्यवस्था को कमजोर किया है। कई बार मुफ्त दवाएं मरीजों तक नहीं पहुंचतीं, मशीनें अनुपयोगी पड़ी रहती हैं, जांचों में देरी होती है और मरीज अस्पतालों के चक्कर लगाते-लगाते टूट जाता है। गरीब व्यक्ति के लिए बीमारी केवल शारीरिक पीड़ा नहीं रहती, बल्कि आर्थिक और मानसिक संकट भी बन जाती है। आज एक और गंभीर संकट सामने आया है-डॉक्टर बनने की अंधी दौड़ और शॉर्टकट संस्कृति। नीट जैसी परीक्षाओं में धांधलियों ने पहले ही देश को झकझोर दिया है। यदि प्रवेश प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए और उसके बाद फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर व्यवस्था में प्रवेश करने लगें,तो यह पूरे चिकित्सा तंत्र की विश्वसनीयता को समाप्त कर देगा। डॉक्टर बनने के पीछे वर्षों की कठिन पढ़ाई,प्रशिक्षण,अनुशासन और संवेदनशीलता की साधना होती है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को धन, भ्रष्टाचार और जालसाजी से बदल दिया जाएगा तो परिणाम केवल भयावह ही होंगे। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य संकट नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक विश्वास का संकट भी है। जब नागरिक डॉक्टर की योग्यता पर संदेह करने लगें, अस्पतालों में भय के साथ प्रवेश करें और दवा खरीदते समय उसकी प्रामाणिकता को लेकर आशंकित रहें,तब यह किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक संकेत है। स्वास्थ्य व्यवस्था में विश्वास टूटना समाज की आत्मा पर चोट पहुंचाने जैसा है। दुनिया के विकसित देशों में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अपराधों को अत्यंत गंभीर माना जाता है। वहां फर्जी चिकित्सकों को केवल नौकरी से नहीं हटाया जाता,बल्कि आजीवन प्रतिबंध, भारी आर्थिक दंड और आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ता है। कई देशों में डॉक्टरों के पंजीकरण और प्रमाणपत्रों का नियमित सत्यापन होता है तथा डिजिटल निगरानी व्यवस्था इतनी मजबूत होती है कि फर्जीवाड़े की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसके विपरीत भारत में कई बार जांच प्रक्रिया लंबी,जटिल और धीमी होती है। वर्षों तक जांच चलती रहती है और दोषी बच निकलते हैं। यह व्यवस्था अपराधियों में भय नहीं,बल्कि निर्भीकता पैदा करती है। अब समय केवल चिंता व्यक्त करने या औपचारिक आश्वासनों का नहीं,बल्कि निर्णायक और कठोर कदम उठाने का है। देश के प्रत्येक पंजीकृत डॉक्टर का लाइव डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए,जहां कोई भी नागरिक एक क्लिक पर डॉक्टर की योग्यता, पंजीकरण संख्या, मेडिकल कॉलेज और सेवा विवरण की पुष्टि कर सके। मेडिकल काउंसिलों को केवल कागजी संस्थाएं नहीं,बल्कि सक्रिय निगरानी तंत्र बनाना होगा। अस्पतालों का नियमित निरीक्षण हो,डॉक्टरों के दस्तावेजों का रैंडम फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए और फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर केवल फर्जी डॉक्टर ही नहीं,बल्कि उसके दस्तावेज पास करने वाले अधिकारी और सत्यापन करने वाले कर्मचारी भी सह-आरोपी बनाए जाएं। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा में नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को पुनर्स्थापित करना होगा। चिकित्सा केवल रोजगार नहीं,सेवा का क्षेत्र है। डॉक्टर का पहला धर्म लाभ कमाना नहीं, जीवन बचाना होना चाहिए। यदि चिकित्सा क्षेत्र से संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी तो मशीनें बचेंगी,मानवता नहीं। आज समाज एक गहरे भय और असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं,जब जीवन बचाने वाले ही जीवन के लिए खतरा बन जाएं,जब अस्पतालों में भरोसे की जगह डर और संदेह बैठ जाए,तब नागरिक कहां जाए? यह प्रश्न केवल मध्यप्रदेश और राजस्थान तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे देश के सामने खड़ा है। यह केवल चिकित्सा व्यवस्था की समस्या नहीं,बल्कि नैतिक पतन और सामाजिक विघटन का संकेत है। वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं बनेगा। वह तभी बनेगा जब नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे,जब अस्पताल आशा के केंद्र बनेंगे,जब दवा पर विश्वास होगा और जब डॉक्टर का नाम सुनते ही श्रद्धा और भरोसा जागेगा। सड़कें,उद्योग, तकनीक और पूंजी महत्वपूर्ण हैं,लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का जीवन है। यदि जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो विकास का कोई भी सपना अधूरा रह जाएगा। मेडिकल जैसे पवित्र पेशे में घुस चुके भ्रष्टाचार,फर्जीवाड़े और अनैतिकता के इस कैंसर का उपचार समय रहते करना होगा। यह केवल कानून का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का प्रश्न है। यदि हमने समय रहते कठोर निर्णय नहीं लिए तो फर्जी चिकित्सकों,नकली दवाओं और मुनाफाखोरी का यह जाल समाज के विश्वास को पूरी तरह निगल जाएगा। विकसित भारत की यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता, शुचिता, जवाबदेही और मानवीयता सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जहां जीवन सुरक्षित नहीं,वहां विकास का कोई भी स्वप्न स्थायी नहीं हो सकता।

राहुल-अखिलेश पर टिकी 2029 की राजनीति

अजय कुमार,
लखनऊ (उ. प्र.)

2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब देश ने विपक्षी गोलबंदी का एक महा-प्रयोग देखा था, तब उसका नाम था 'इंडिया गठबंधन' । यह प्रयोग बिना संदेह बड़ा था। 26 प्रमुख विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह रही कि इसे कभी कोई सर्वमान्य चेहरा या नेतृत्व नहीं मिल सका। 'विपक्ष का दूल्हा कौन बनेगा?' यह अंतहीन कलह गठबंधन की बुनियाद को ही खोखला करती रही। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए तो ममता बनर्जी वीटो लगा देती हैं, राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनती ही नहीं। नतीजा यह निकला कि बिखरा हुआ विपक्ष अपने-अपने राज्यों के किलों में सिमटकर रह गया,जिन्हें बीजेपी एक-एक करके ढहा रही है। आज जैसे-जैसे विपक्षी धुरंधर बारी-बारी चुनावी बिसात पर धराशायी हो रहे हैं,राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस का 'डिफॉल्ट' दावा एक बार फिर पूरी ताकत से जिंदा हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का हालिया बयान इसी नैरेटिव की बानगी है। उन्होंने राहुल गांधी को 2029 का 'प्राइम-चैलेंजर' घोषित कर दिया है और कहा कि कांग्रेस सबसे पहले अपने सहयोगियों से इस बात पर सहमति बनाएगी। रेवंत की थ्योरी दिलचस्प है। वे लेफ्ट और क्षेत्रीय क्षत्रपों की हार में कांग्रेस की जीत देख रहे हैं। विडंबना यह है कि ये वही दल हैं जो कल तक 'इंडिया गठबंधन' में कांग्रेस के साझेदार थे और आज अपने-अपने राज्यों में बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। लोकसभा में टीएमसी ने किला बचा लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की चौखट पर आते ही बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने उनकी सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। बीजेपी ने यहां 206 सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी 100 से नीचे लुढ़क गई। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से 15 हजार से ज्यादा वोटों से हार गईं। हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को भले वहां दो सीटें मिलीं,लेकिन उसे इस बात का सुकून है कि बंगाल में अब टीएमसी का एकाधिकार खत्म हो चुका है। दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने वाले अरविंद केजरीवाल का सपना 'तीसरा विकल्प' बनने का था। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी। 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की,जबकि आप 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस आज इस गणित पर खुश हो सकती है कि जो भी जमीन आप खोएगी, वह आखिरकार कांग्रेस की झोली में ही गिरेगी। नीतीश कुमार ने 2024 से पहले विपक्ष को एक धागे में पिरोने के लिए देशव्यापी दौरे किए थे, लेकिन केंद्रीय राजनीति में उनका नेतृत्व स्थापित होने से पहले ही सहयोगियों के अविश्वास ने उनकी जमीन खिसका दी। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

अब रह गई केवल एक दीवार अखिलेश यादव। वे राहुल गांधी के लिए एक जटिल पहेली हैं। चुनौती इसलिए हैं क्योंकि वे देश के सबसे बड़े सियासी सूबे,उत्तर प्रदेश,के निर्विवाद नायक हैं। यह वही यूपी है जिसने 2024 में बीजेपी के रथ को रोककर उसे बहुमत से दूर कर दिया था। अखिलेश आज विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पास कोर 'मुस्लिम-यादव' वोटबैंक की अचूक ताकत है, एक मजबूत संगठन है और वे सीधे योगी-मोदी की जोड़ी की आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे हैं। 2024 में कांग्रेस को यूपी में जो भी संजीवनी मिली,उसका पूरा श्रेय अखिलेश के खाते में जाता है। इस कड़वे सच के बावजूद,राहुल गांधी के लिए राहत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ कभी वह 'अहंकार और तिरस्कार' का रवैया नहीं अपनाया,जो ममता बनर्जी ने बंगाल में दिखाया। अखिलेश खुद यूपी की सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं,इसलिए वे दिल्ली की रेस के लिए कांग्रेस से फिलहाल कोई नया मोर्चा नहीं खोलना चाहते।

असल परीक्षा 2027 में होगी। यदि अखिलेश 2027 में यूपी फतह कर लेते हैं, तो वे राष्ट्रीय क्षितिज पर राहुल गांधी से कहीं बड़े कद के नेता बनकर उभरेंगे। वे 2027 की तैयारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूपी में अगले वर्ष समाजवादी सरकार बनने जा रही है। लेकिन यदि वे नाकाम रहे, तो राहुल गांधी 2029 के लिए 'निर्विरोध चैलेंजर' बन जाएंगे। क्षेत्रीय दलों की त्रासदी यह है कि उनकी प्रासंगिकता सिर्फ उनके राज्य की सत्ता से है, जबकि कांग्रेस के लिए 'ब्रांड राहुल' राज्यों की हार-जीत के नफे-नुकसान से बहुत ऊपर है। 2024 में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने ऐसा जश्न मनाया था, मानो देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने पुराने वैभव में लौट आई हो। लेकिन यह भ्रम जल्द ही टूट गया। हरियाणा में जीत का हलवा तैयार था, पर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और बीजेपी की माइक्रो-प्लानिंग ने बाजी पलट दी। इसके बाद पराजय का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर खिसक गई। गनीमत बस इतनी रही कि उसके मजबूत सहयोगी राजद,उद्धव शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी खुद को बचा नहीं पाए। तमिलनाडु में जब डीएमके का जहाज डूबने लगा, तो चतुर कांग्रेस ने समय रहते पाला बदलकर पांच विधायकों के साथ सत्ता के नए जहाज पर छलांग लगा दी। हाल ही में डीएमके ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की घोषणा की है और लोकसभा में अलग बैठने की मांग की है। डीएमके और कांग्रेस का 20 साल पुराना रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। पूरी तस्वीर का सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी पहलू यही है कि देशभर में स्थितियां कांग्रेस के अनुकूल हो रही हैं,लेकिन इस खेल में कांग्रेस का अपना कोई पराक्रम नहीं है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्षेत्रीय दलों और वामपंथ के जिस सफाए पर संतोष जता रहे हैं, वह जमीन कांग्रेस ने नहीं,बल्कि बीजेपी ने जीती है। बिहार में नीतीश,बंगाल में ममता,दिल्ली में केजरीवाल और अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं,तो 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश बीजेपी एक-एक करके राहुल के सभी आंतरिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा रही है। लब्बोलुआब यह है कि यदि राहुल गांधी की उम्मीदें अपने संगठन की ताकत से ज्यादा बीजेपी की आक्रामक विस्तारवादी नीति पर टिकी हैं, तो यह बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी की राह के कांटे खुद पीएम मोदी ही दूर कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी को विपक्ष का इकलौता सुल्तान बनाने का सेहरा, अनजाने में ही सही, बीजेपी के सिर ही सजेगा। विपक्ष का भविष्य अब अखिलेश यादव और 2027 के यूपी चुनाव पर टिका है यही राजनीति का चक्रव्यूह है।

पचाने वाली चूरन की पुड़िया

आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

हमारे देश में जहाँ लोगों को भरपेट भोजन न मिले,वहाँ पचाने वाली चूरन की पुड़िया का आविष्कार कर उसका व्यापार पूरे देश-दुनिया में सफलतापूर्वक चलाने वाले गुणी व्यापारी को सच मायने में देश के सर्वोच्च पुरूस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए, पर क्या कीजिएगा हमारे देश में क्रांति लाने वाले योग्य को सम्मान देने पर किसी ने विचार नहीं किया। पचाने के इस आविष्कार का लाभ हवाबाण हरडे ने दिया। हवाबाण मतलब सब हवा में, हवाहवाई होना। पेट गले तक भरा है, डकार अर्थात हवा तक नहीं आ रही है तब ऐसे में हवाबाण हरडे पूरन की पुड़िया खाते ही पेट का खाना हवाहवाई हो जाएगा। देश में पचाने की पुडिया क्या आई कि व्यापारियों ने चूरन खाकर काला धन जमा कर धन को पचाने की ताकत पा ली। बस गरीब को छोड़कर सारे बड़े व्यापारी, पूंजीपति चूरन खाकर काली कमाई के सिकन्दर हो गए,सभी भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत पचाने लगे, पुलिसवाले कानून पचाने लगे। नेता समूचा देश पचाने लगे,जनता सोसलमीडिया पर फैलाये गए कचरे गंदगी को पचाने में ऐसी सोयी हुई है कि वह घर का शुद्ध स्वास्थवर्धक खाना छोड़ चुकी है।

बचपन में हवाबाण हरडे चूरन की पुड़िया खाकर खट्टी मीठी डकार लेने का मजा ही कुछ और था भले पेट में अन्न का दाना नहीं हो,पर शोक नबावी था इसलिए जरूरी नहीं की नबावों की तरह पेट को कूडेदान समझकर अनाप-शनाप न खाने योग्य सामग्री से पूरा भर लिया जाए, जिसमें सांस लेने तक में दिक्कत हो, किन्तु बचपन में हवा के गोले नहीं छूटते थे। देश की सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज देती है पर बाजार में इतनी ज्यादा मॅहगाई है कि भरपेट खाने के लिए दिनभर की मजदूरी कम पड जाए, इसलिए गरीब भी सरकार से ज्यादा चतुर हो गया है इसलिए वह मुफ्त मिलने वाले अनाज को औने-पौने दामों में बेचकर तुरन्त देशी ठर्रे की दुकान पर पहुंच जाता है। गरीब जानता है कि मॅहगाई इतनी है कि बच्चों को पढ़ा नहीं सकते,इसलिए वह पैदा होने के बाद से बच्चें को आत्मनिर्भर बनाने क लिए मेहनत मजदूरी करने काम पर लगा देता है। गरीब भी मजेदार होते है भले पेट न भरे पर नशे के सारे शोक उनपर सवार होते है और बच्चे नशे में धुत्त नशा पचाने अर्थात उतारने के लिए चूरन की पुड़िया खाने को विवश होते है।

संजय एम तराणेकर
इन्दौर-(मध्य प्रदेश)

मोबाइल में खोया बचपन...!

यूं किताबें हैं सामने खुली पड़ी,
पर नजरें 'स्क्रीन' में अटकी हैं।
वो बचपन की मीठी किलकारी,
आजकल मोबाइल में सिमटी हैं।

अब ना मैदानों की वह दौड़ रही,
ना पेड़ोंवाली ठंडी-सी छाँव रही।
उन उँगलियों के छोटे 'स्पर्शों' में,
तब सारी दुनिया ही सिमटी रही।

वो ही 'माँ' की बातें आधी सुनते,
पापा का 'स्नेह' भी कम लगता।
'गेम और वीडियो' की दुनिया से,
हर पल उन्हें सब 'प्रिय' लगता।

यहाँ 'ज्ञान' मिले तो अच्छी बात,
तकनीक के साथ 'वरदान' बने।
पर ये मोबाइल की अंधी आदत,
बचपन का तो नुकसान ना बने।

आओं चलो फिर से खेल सजाएँ,
चलकर मिट्टी में सपने बोएँ हम।
वर्तमान मोबाइल से थोड़ा दूर हटें,
हँसता-गाता बचपन संजोएँ हम।

सुविचार

कार पर सस्ता,शिक्षा पर ब्याज भारी क्यों?

डॉ. प्रियंका सौरभ
आर्यनगर
हिसार,हरियाणा

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को हमेशा राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। हम अक्सर यह कहते हैं कि युवा देश का भविष्य हैं, शिक्षा समाज की रीढ़ है और ज्ञान ही विकास का आधार है। लेकिन जब व्यवहारिक व्यवस्था को देखा जाता है,तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। विडंबना यह है कि आज भारत में कार खरीदना आसान होता जा रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगातार कठिन और महँगा होता जा रहा है। बैंक आपको नई कार खरीदने के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर तुरंत ऋण देने को तैयार मिल जाएंगे,परंतु वही बैंक जब किसी विद्यार्थी को शिक्षा ऋण देते हैं,तो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं,नियम कठोर हो जाते हैं और भविष्य को जोखिम मान लिया जाता है। यह स्थिति केवल बैंकिंग प्रणाली की तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी है। आज भारत में उच्च शिक्षा का खर्च सामान्य परिवारों की सामर्थ्य से तेजी से बाहर होता जा रहा है। मेडिकल,इंजीनियरिंग,मैनेजमेंट,लॉ,निजी विश्वविद्यालयों की पढ़ाई या विदेश में शिक्षा–हर क्षेत्र में फीस लाखों में पहुँच चुकी है। मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों की बचत लगा देते हैं,गहने बेचते हैं, भविष्य निधि तोड़ते हैं,फिर भी शिक्षा ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि जिस शिक्षा से एक युवा का भविष्य बनना है,उसी पर सबसे अधिक ब्याज का बोझ लाद दिया जाता है। कार लोन की ब्याज दरें कई बार शिक्षा ऋण से कम होती हैं। अर्थात एक उपभोक्ता वस्तु खरीदना शिक्षा प्राप्त करने से सस्ता पड़ता है। यह केवल आर्थिक असंतुलन नहीं,बल्कि सामाजिक सोच की भी त्रासदी है। बैंकिंग व्यवस्था का तर्क यह होता है कि कार लोन सुरक्षित होता है क्योंकि वाहन बैंक के लिए गिरवी संपत्ति का काम करता है। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति भुगतान न करे,तो कार जब्त की जा सकती है। लेकिन शिक्षा ऋण में बैंक के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। वहाँ केवल छात्र की योग्यता,उसकी डिग्री और उसका भविष्य होता है। इसलिए बैंक इसे जोखिमपूर्ण निवेश मानते हैं। यह तर्क बैंकिंग दृष्टि से भले सही प्रतीत हो, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत संकीर्ण है। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा निवेश उसकी युवा पीढ़ी होती है। एक छात्र जब डॉक्टर, इंजीनियर,वैज्ञानिक,शिक्षक, शोधकर्ता या प्रशासक बनता है,तो उसका लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं होता,पूरा समाज उससे लाभान्वित होता है। ऐसे में शिक्षा ऋण को केवल व्यापारिक उत्पाद की तरह देखना दूरदर्शिता नहीं कहलाएगा। वर्तमान समय में शिक्षा ऋण केवल आर्थिक सहायता नहीं,बल्कि मानसिक दबाव का कारण भी बनता जा रहा है। लाखों विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही ईएमआई और ब्याज की चिंता में घिर जाते हैं। नौकरी मिलने से पहले ही कर्ज का भय उन्हें परेशान करने लगता है। कई छात्र अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार करियर चुनने के बजाय केवल अधिक वेतन वाली नौकरियों की ओर इसलिए भागते हैं ताकि ऋण चुका सकें। परिणामस्वरूप शोध,अध्यापन, साहित्य,सामाजिक सेवा और कला जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं की संख्या घटती जा रही है। समाज धीरे-धीरे केवल वेतन आधारित सफलता का समर्थक बनता जा रहा है। इस समस्या का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय मध्यमवर्ग पर पड़ता है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार महँगी शिक्षा का खर्च आसानी से उठा लेते हैं। गरीब वर्ग के लिए सरकार की कुछ योजनाएँ और छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। लेकिन सबसे अधिक संघर्ष उस वर्ग को करना पड़ता है जो 'गरीब' की श्रेणी में नहीं आता,फिर भी लाखों रुपये की फीस वहन करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे परिवारों के लिए शिक्षा ऋण मजबूरी बन जाता है। एक पिता पूरी जिंदगी की कमाई बेटे या बेटी की पढ़ाई में लगा देता है,इस उम्मीद के साथ कि शिक्षा भविष्य को सुरक्षित करेगी। लेकिन जब उसी शिक्षा पर भारी ब्याज लग जाता है,तो वह सपना धीरे-धीरे आर्थिक बोझ में बदलने लगता है। आज भारत में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ा है। सरकारी संस्थानों की सीमित सीटों के कारण लाखों छात्रों को निजी कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। वहाँ फीस इतनी अधिक होती है कि सामान्य परिवारों के लिए बिना ऋण के पढ़ाई संभव नहीं रह जाती।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

सरगुजा में एक बार फिर भीषण गर्मी,तापमान 41 डिग्री के करीब

■ दोपहर में घर से निकलना हुआ मुश्किल,शरीर झूलसा देने वाली पड़ रही गर्मी

■ मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और बढ़ेगा अधिकतम तापमान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पिछले दो दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह 10 बजे के बाद ही सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। पिछले सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिला था। आंधी और हल्की बारिश के कारण तापमान गिरकर 36 से 37 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन सोमवार से मौसम साफ होते ही गर्मी अचानक बढ़ गई। सोमवार को तापमान 40 डिग्री पहुंचा, जबकि मंगलवार को इसमें और वृद्धि दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक

एसके मंडल ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। आने वाले दिनों में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। सरगुजा संभाग इस समय लू की चपेट में है और देर शाम तक गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की ओर से आ रही गर्म और शुष्क हवाओं के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर सरगुजा संभाग में साफ दिखाई दे रहा है।

रात में भी नहीं मिल रही राहत

दिन के साथ रात में भी उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। पंखे और कूलर से भी गर्म हवा निकल रही है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। दिन और रात में घंटों बिजली बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लटोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के 9 कर्मचारियों को नोटिस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने सोमवार रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आपातकालीन ड्यूटी में तैनात चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित मिले। अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के नोटिस बोर्ड में इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर, स्टाफ नर्स एवं अन्य कर्मचारियों की अद्यतन जानकारी नहीं मिली। इस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि जिन मरीजों का इलाज स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें अनावश्यक रूप से रेफर न किया जाए। यदि रेफर करना जरूरी हो तो निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कारण सहित मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेजा जाए। निरीक्षण में अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित जागरूकता सामग्री और आईईसी फ्लेक्स भी कम संख्या में पाए गए। अधिकारियों को इन्हें बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। डॉ. शुक्ला ने हीट वेव को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने तथा नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उपस्थिति पंजी के अवलोकन में 9 अधिकारी-कर्मचारी पूर्व दिनों में अनुपस्थित पाए गए। इस पर संस्था प्रभारी सहित संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उदयपुर वन परिक्षेत्र में 13 हाथियों का दल पहुंचा,फसल नुकसान का आंकलन जारी

-संवाददाता-
उदयपुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

वन परिक्षेत्र उदयपुर के बासेन सर्किल अंतर्गत सरमा बीट क्षेत्र में 13 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को हाथियों का दल चकेरी बीट के कक्ष क्रमांक 2056 से होते हुए सरमा बीट के पीएफ 2061 क्षेत्र में पहुंचा, जहां दल वर्तमान में विचरण कर रहा है। बताया गया है कि हाथियों के दल द्वारा चकेरी गांव में फसल नुकसान किया गया है,जिसका आंकलन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 कृषक प्रभावित हुए

हैं। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि, मकान क्षति, झोपड़ी नुकसान अथवा पशु हानि की सूचना नहीं है। वन विभाग के अनुसार यह दल कोरबा एचई-2 नाम से चिन्हित है, जिसमें 1 नर, 6 मादा एवं 6 शावक शामिल हैं। कुल 13 हाथियों का दल क्षेत्र में मौजूद है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन अमला लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी एवं प्रचार-प्रसार कर लोगों को सतर्क कर रहा है। ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने, मवेशी चराने, जलाऊ लकड़ी एवं तेंदूपत्ता संग्रहण से फिलहाल बचने की अपील की गई है। वन विभाग ने चकेरी,बासेन,परसा, सनिबर्रा एवं सरमा सहित आसपास के गांवों को संभावित प्रभावित क्षेत्र बताया है। दल प्रभारी के रूप में परिक्षेत्र सहायक बासेन एवं स्टाफ निगरानी में जुटे हुए हैं।

जिले में अपराध पर नियंत्रण लाने रात्रि गस्त एवं वाहनों के नियमित चेकिंग के दिए गए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ट पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा जिले के समस्त अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की वर्चुअल मीटिंग ली गई। इस बैठक मे मुख्य रूप से शहर एवं शहर से लगे क्षेत्रों में अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रात्री में नियमित गश्त एवं वाहनों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिये। थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में आगंतुकों की चेकिंग एवं संचालित होटल, लॉज ढाबा, बस स्टैण्ड इत्यादि की चेकिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिये

गए। जिले के विभिन्न थानों में अपराधों की समीक्षा की गई, लम्बित अपराधों में विशेषज्ञों की रे लेकर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध पंजिबद्ध अपराध में प्रभारी एवं शीध्र कार्यवाही करना निर्देशित किया गया साथ ही थानो में लंबित अपराधों की नियमित विवेचना कार्यवाही करने,वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री अमोलक सिंह ढिल्लो, नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर श्री राहुल बंसल, उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री तुल सिंह पट्टावी, थाना प्रभारी कोतवाली अम्बिकापुर निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रविण द्विवेदी, थाना प्रभारी अजाक निरीक्षक अजय खेस, थाना प्रभारी महिला थाना उप निरीक्षक सुनिता भारद्वाज, प्रभारी साइबर सेल अम्बिकापुर सहायक उप निरीक्षक अजीत कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी उपस्थित रहें शेष ग्रामीण छेत्र के थाना प्रभारियों को ऑनलाईन मीटिंग ली गई।

प्रदेश की जूनियर बालक बास्केटबॉल टीम में सरगुजा के विक्की भगत का चयन

संघर्ष से नेशनल तकः फल बेचने वाले विक्की भगत का जूनियर नेशनल बास्केटबॉल में चयन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के लिए गर्व का विषय है कि जिले के होनहार एवं मेहनती खिलाड़ी विक्की भगत का चयन प्रदेश की जूनियर बालक बास्केटबॉल टीम में हुआ है। विक्की अब पुडुचेरी में आयोजित होने वाली 76वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 22 मई से 29 मई 2026 तक आयोजित होगी। विक्की पिछले कई वर्षों से गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में नियमित अभ्यास कर रहा है। इस उपलब्धि पर अनिल सिंह मेजर, आदित्यायेश्वर शरण सिंह, गौरव सिंह, केपी सिंह, सौरभ सिंहा, निशांत सिंह, रजत सिंह सहित सरगुजा जिला बास्केटबॉल संघ के सभी पदाधिकारियों, खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों ने विक्की भगत को शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

एमआईसी बैठक के प्रस्ताव हास्यास्पद, जनता के मुद्दों से भटक रही भाजपा सरकार : द्वितेन्द्र मिश्र

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

नगर निगम एमआईसी बैठक में पारित प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। निगम एमआईसी के पूर्व सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव द्वितेन्द्र मिश्र ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करने वाली भाजपा अब जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है और निगम प्रशासन अपरिपक्व फैसले ले रहा है। द्वितेन्द्र मिश्र ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरा एशिया वैश्विक आर्थिक संकट से प्रभावित है,निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार वृद्धि

हो रही है और केंद्र सरकार तक निर्माण कार्यों के लिए विशेष मूल्य वृद्धि संबंधी सर्कुलर जारी कर रही है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा ठेके निरस्त करने और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने जैसे प्रस्ताव पारित करना हास्यास्पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में पिछले लगभग 18 महीनों से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। ऐसे में निगम प्रशासन को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं और उनके परिवारों की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय राजनीतिक दिखावा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पूर्व परिषद के पार्षदों का मानदेय भुगतान तक लंबित है। उन्होंने मांग की कि ट्रिपल इंजन सरकार के प्रतिनिधि शासन से तत्काल राशि उपलब्ध कराकर सफाई कर्मियों का भुगतान सुनिश्चित करें और निर्माण कार्यों को केंद्र सरकार के सर्कुलर के अनुरूप मूल्य वृद्धि स्वीकृति देकर पूरा कराएं।

प्रेस विज्ञप्ति में शहर की मूलभूत समस्याओं को भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें अब तक निगम में शामिल नहीं हो पाई हैं, पेयजल संकट बना हुआ है और प्रतिदिन घंटों बिजली कटौती हो रही है। बरसात से पहले नालियों की सफाई अभियान चलाने की आवश्यकता है, लेकिन इन मुद्दों पर कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही। द्वितेन्द्र मिश्र ने भाजपा सरकार पर चुनावी वादों को भूलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को मुफ्त पट्टा देने के बजाय जगह-जगह बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता से किए गए वादे पूरे करने चाहिए,न कि केवल राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए।

कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान गिरी लोहे की जाली,प्लांट सील...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेलाई स्थित क्रशर प्लांट में काम के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान हुआ, जब मजदूर के ऊपर भारी लोहे की जाली गिर गई। गंभीर रूप से घायल मजदूर को इलाज के लिए अंबिकापुर लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम खाराकोना निवासी 20 वर्षीय अल्मोन पिता संतू अन्य मजदूरों के साथ सिंघल क्रशर प्लांट में काम करता था। शनिवार दोपहर उसे कन्वेयर बेल्ट

की सफाई का काम दिया गया था। इसी दौरान अचानक भारी जाली उसके ऊपर गिर गई और वह दब गया। मौके पर मौजूद मजदूरों ने गैस कटर से जाली काटी और जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाला। एंबुलेंस नहीं मिलने पर घायल मजदूर को निजी वाहन से अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

प्रशासन ने प्लांट किया सील : घटना की सूचना मिलते ही खनिज विभाग की टीम और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने संबंधित क्रशर मशीन को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया है। श्रम विभाग और इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ सेफ्टी विभाग द्वारा भी जांच शुरू कर दी गई है।

सचालक पर हो सकती है कार्रवाई : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच में लापरवाही सामने आने पर क्रशर संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शादी में गए परिवार के सूने मकान में चोरी,शातिर चोर गिरफ्तार

ताला तोड़कर सोने के जेवर,नगदी और चावल की बोरी ले गया था आरोपी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी गया सोने का लॉकेट बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गांधीनगर हाई स्कूल के पीछे रहने वाला परिवार 14 मई को रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गया था। घर में ताला बंद था। 17 मई को वापस लौटने पर मकान का मुख्य दरवाजा और पेटी का ताला टूटा मिला। घर से सोने का एक लॉकेट, दो जोड़ी कान की बाली, 2 हजार रुपए नगद और चावल की बोरी चोरी हो चुकी थी। प्रार्थी की शिकायत पर थाना गांधीनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध युवक बनारस रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी की पहचान भज्जू वासुदेव उर्फ लल्लू, निवासी सहायकपुर चौकी

करंजी थाना विश्रामपुर जिला सूरजपुर के रूप में हुई। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सोने का लॉकेट बरामद किया गया। बाद में उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ चोरी, नकबजनी, जुआ एक्ट और अन्य मामलों सहित करीब 24 अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वह पहले भी गांधीनगर, विश्रामपुर और सूरजपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी, सहायक उपनिरीक्षक सुभाष ठाकुर, अभिषेक दुबे, आरक्षक कुंदन पांडेय और राहुल सिंह की अहम भूमिका रही।

कक्षा 9वीं,10वीं व 12वीं के मेधावी छात्रों को मिलेगा निःशुल्क आवासीय कोचिंग का अवसर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित सरगुजा-30 कोचिंग योजना के तहत चयन परीक्षा का आयोजन 21 मई को किया जाएगा। परीक्षा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा में जिले के शासकीय हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 12वीं (गणित व जीव विज्ञान संकाय) के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। पात्रता के लिए पिछली कक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य रखा गया है। विद्यार्थियों को अंकसूची की छायाप्रति,पालक की सहमति तथा विद्यालय परिचय पत्र साथ लाना होगा। चयन परीक्षा केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होगी। विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म में परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य रहेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को सुबह 10 बजे तक केंद्र में उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

मेरिट के आधार पर चयनः मेरिट के आधार पर कक्षा 9वीं के 30, कक्षा 10वीं के 10 तथा कक्षा 12वीं के 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को सरगुजा-30 योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क आवासीय कोचिंग दी जाएगी।

किराए के मकान में महिला की संदिग्ध मौत...ट्रांसपोर्टनगर में अर्द्धनग्न हालत में मिला शव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 मई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के ट्रांसपोर्टनगर क्षेत्र स्थित किराए के मकान में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव कमरे में अर्द्धनग्न अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर मणिपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीतापुर क्षेत्र की रहने वाली 32 वर्षीय सुखमनिया चिकवा अपने पति जमुना और दो बच्चों के साथ कदमपारा स्थित किराए के मकान में रहती थी। उसका पति हमाली का काम करता है। बताया जा रहा है कि रात में दोनों साथ में सोए थे। सुबह पति काम पर चला गया। सुबह काफी देर तक महिला घर से बाहर नहीं निकली तो मकान मालकिन और पड़ोसियों ने कमरे में जाकर देखा। वहां महिला औंधे मुंह पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जांच में महिला के शरीर पर चोट या गला दबाने के निशान नहीं मिले हैं। शुरुआती जांच में अत्यधिक शराब सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं बच्चों और मकान मालकिन का बयान भी दर्ज किया गया है।

नाम परिवर्तन सूचना

मै जियान एस्थेर एक्का (माता/पिता/ पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री स्व0 सपन एक्का गाँव/शहर डुगडुगिया पोस्ट कुनकुरी तहसील कुनकुरी जिला जशपुर,छ0ग0 राज्य ने, अपने नाबालिग बहन का नाम जायेस टिना एक्का (पुराना नाम) से बदल कर जायस एक्का (नया नाम) रख लिया है।

पालक
जियान एस्थेर एक्का
कुनकुरी जिला जशपुर,छ0ग0

डीईओ के आदेश की खुली अवहेलना...महुली हाई स्कूल में लटका मिला ताला,ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी कार्यालय खोलने के निर्देश बेअसर

विद्यार्थियों और अभिभावकों को हो रही भारी परेशानी...ग्रामीणों ने जांच कर कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/चांदनी बिहारपुर,19 मई 2026 (घटती-घटना)। जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के कार्यालय नियमित रूप से खोलने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों की खुलेआम अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया है,चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल महुली में कार्यालय समय के दौरान ताला लटका मिला,जिससे ग्रामीणों, विद्यार्थियों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में न तो शिक्षक मौजूद थे और न ही कोई कार्यालयीन कर्मचारी,जबकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में भी विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यालय खुला रखा जाए।

15 मई को जारी हुआ था आदेश

जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा 15 मई 2026 को आदेश क्रमांक 4173 जारी किया गया था,आदेश में जिले के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी), अंकसूची वितरण तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय कार्यालय नियमित रूप से संचालित किए जाएं, आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया था कि कार्यालयीन कार्यों के संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि विद्यार्थियों और पालकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

आदेश के बावजूद स्कूल में लटका रहा ताला

ग्रामीणों के अनुसार सोमवार को जब वे आवश्यक कार्यों के लिए शासकीय हाई स्कूल महुली पहुंचे,तो विद्यालय परिसर में ताला लगा मिला। कई विद्यार्थी और अभिभावक घंटों तक विद्यालय परिसर में इंतजार करते रहे,लेकिन कोई जिम्मेदार शिक्षक या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा,इस घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई। लोगों का कहना है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी का स्पष्ट आदेश मौजूद है,तब भी विद्यालय प्रशासन द्वारा आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।

विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप

अभिभावकों का कहना है कि वर्तमान समय में कई विद्यार्थियों को प्रवेश,छात्रवृत्ति,दस्तावेज सत्यापन और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए टीसी एवं अंकसूची की तत्काल आवश्यकता पड़ती है,विद्यालय बंद रहने से छात्रों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है,कई विद्यार्थी दूसरे विद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं,ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि यदि जिला स्तर से जारी आदेशों का पालन ही नहीं हो रहा,तो फिर ऐसे आदेशों का औचित्य क्या रह जाता है, लोगों का कहना है कि कई बार सरकारी आदेश केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती,ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी शिक्षकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो।

अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें...

मामले के सामने आने के बाद अब लोगों की निगाहें सूरजपुर कलेक्टर और शिक्षा विभाग पर टिकी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती,तो इससे अन्य विद्यालयों में भी आदेशों की अनदेखी को बढ़ावा मिलेगा,लोगों ने मांग की है कि स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था मजबूत की जाए और ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कार्यालय संचालन की नियमित मॉनिटरिंग हो, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

ग्राम भिट्टीकला के भूमि संबंधी प्रकरण में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय पर लगी रोक

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 मई 2026 (घटती-घटना)। कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा ग्राम भिट्ठीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790 रकबा कुल 1.271 एकड़ भूमि के संबंध में प्राप्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने तथा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जारी अदेशानुसार आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव बेवा स्व. बंधन यादव निवासी भिटठीलकला महुवाटिकरा तहसील अम्बिकापुर द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिटठीकला तहसील अम्बिकापुर मे भूमि खसरा कमांक 782, 783, 790 रकबा क्रमशः 0.680, 0.502, 0.089 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि स्थित है। आवेदिका व अनावेदक कमांक-01 पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाईफ स्टाईल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) के मध्य उपरोक्त भूमि मे से मात्र 24 डिसमिल भूमि को राशि 3.00 लाख रूपये प्रति डिसमिल के दर पर कुल 72.00 लाख रूपये मे विकय का सौदा हुआ था, परंतु अनावेदक कमांक 02 से 06 अनावेदक कमांक (2) सागर विश्वकर्मा आ. अज्ञात (3) डोमन राजवाड़े आ. प्रभु (4) जीतन विश्वकर्मा आ. अज्ञात (5) आशीष उर्फ बाबा आ. अज्ञात एवं संजय गुप्ता आ. बसंतलाल गुप्ता सभी निवासी भिटठीकला महुआटिकरा तहसील अम्बिकापुर के साथ षड़यंत्र करते हुये आवेदिका के स्वामित्व की सम्पूर्ण

रकबा 1.271 हे. (3.14 एकड़) भूमि का धोखाधड़ी करते हुये फर्जी विकय पत्र दिनांक 15.05.2026 को निष्पादित करा लिया गया है। अतः अनावेदकगण के विरूद्ध तत्काल संबधित थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराते हुये आवेदिका के आवेदन के संबध मे समुचित कार्यवाही की जावे। आवेदिका के आवेदन के संदर्भ मे आवेदिका को समक्ष में सुना गया। विचारोपरांत आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव बेवा स्व. बंधन यादव निवासी भिटठीलकला महुवाटिकरा तहसील अम्बिकापुर के स्वामित्व की ग्राम भिटठीकला तहसील अम्बिकापुर मे स्थित भूमि खसरा कमांक 782,783,790 रकबा क्रमशः 0.680,0.502, 0.089 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि के कय-विक्रय पर आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिये रोक लगाई जाती है एवं उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाये जाने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर को मामले की जांच कर 7 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

बिना कलेक्टर अनुमोदन 29 दुकानें हस्तांतरित करने का आरोप,11 साल से किराया नहीं वसूले जाने पर उठे सवाल

कम्पनी बाजार की दुकानों को लेकर निगम प्रशासन घिरा,कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर से जांच व कार्रवाई की मांग की

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 मई 2026 (घटती-घटना)। नगर पालिक निगम अंबिकापुर में आईडीएसएमटी योजना के तहत आवंटित दुकानों को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ भाजपा नेता गोधनपुर निवासी कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर सरगुजा को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि कम्पनी बाजार क्षेत्र में रजाई-गद्दा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को वर्ष 2015 में 29 दुकानों का नियम विरुद्ध हस्तांतरण कर दिया गया, जबकि योजना में केवल 'आबंटन' का प्रावधान है, हस्तांतरण का नहीं। शिकायत में कहा गया है कि आईडीएसएमटी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक 39/70/5504/अ.स./न.प्र./2001 रायपुर दिनांक 23 नवंबर 2001 के अनुसार योजना के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं तथा दुकानों के आबंटन के लिए कलेक्टर का अनुमोदन आवश्यक है। आरोप है कि बिना कलेक्टर की स्वीकृति के ही 29 दुकानों को

एक विशेष वर्ग के लोगों के नाम हस्तांतरित कर दिया गया।

11 वर्षों से नहीं लिया गया किराया : आवेदन में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि वर्ष 2015 से अब तक संबंधित दुकानदारों से नगर निगम द्वारा एक रुपये तक का किराया नहीं लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे नगर निगम को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन दुकानों का नियमानुसार संचालन किया जाए तो निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

निगम प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल : मामले के सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। शहर में चर्चा है कि आखिर इतने वर्षों तक दुकानों का किराया क्यों नहीं वसूला गया और बिना सक्षम स्वीकृति के हस्तांतरण कैसे कर दिया गया। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला प्रशासनिक लापरवाही के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता का भी माना जा सकता है। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि शिकायत के बाद इस मामले में जांच समिति गठित होती है या नहीं तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

सामान्य सभा में उठ था मामला,फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

कैलाश मिश्रा ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि यह मामला नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में भी उठ चुका है और जांच कराने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद अब तक किसी प्रकार की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में कई मामलों की जांच की घोषणा तो होती है,लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़तीं। ऐसे में कम्पनी बाजार दुकान हस्तांतरण प्रकरण भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध प्रतीत होता है मामला

शिकायतकर्ता ने कहा है कि जब दुकानों के हस्तांतरण में कलेक्टर का अनुमोदन ही नहीं लिया गया तो पूरा मामला प्रथम दृष्टया अवैध और नियम विरुद्ध प्रतीत होता है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल जांच कराई जाए और नियम विरुद्ध तरीके से हस्तांतरित दुकानों को खाली कराकर पुनःनगर निगम के नियंत्रण में लिया जाए।

NEET परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क विषय आधारित मार्गदर्शन,21 मई से शुरू होंगी कक्षाएं

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 मई 2026 (घटती-घटना)। जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा जिले के ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष निःशुल्क मार्गदर्शन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है,जो NEET 2026 परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तथा परीक्षा स्थगित होने के कारण आगामी 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली छम्म्ज् परीक्षा में शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी अनुसार विषय आधारित निःशुल्क मार्गदर्शन कक्षाएं 21 मई 2026 से मल्टीपर्पज परिसर स्थित S-30 कैम्पस में प्रारंभ की जाएंगी। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थियों का पंजीयन 20 मई 2026 को प्रातः 07:30 बजे से स्-30 कैम्पस, मल्टीपर्पज स्कूल अम्बिकापुर में किया जाएगा। वहीं कक्षाओं का संचालन 21 मई 2026 से प्रतिदिन प्रातः 07:30 बजे से किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं तथा प्रारंभ होने वाली कक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं।

कक्षाओं का संचालन जिले के अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह शिक्षा विभाग की स्वयंसेवी भाव से की जा रही पहल है, जिसका उद्देश्य वर्तमान परिस्थिति में विद्यार्थियों को NEET परीक्षा हेतु बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि जिले के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर जिले का नाम रोशन कर सकें।

सरगुजा के कैंसर मरीजों को बड़ी राहत : वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु गुप्ता फिर देंगे सेवाएं

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 मई 2026 (घटती-घटना)। जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में कैंसर रोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल के अंतर्गत वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु गुप्ता पुनः अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। डॉ. गुप्ता पूर्व में भी नवापारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित दीर्घायु कैंसर वार्ड में सेवाएं दे चुके हैं, जहां उनके अनुभव एवं समर्पण से अनेक मरीज लाभान्वित हुए थे। कलेक्टर अजीत वसंत के विशेष प्रयासों एवं मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप डॉ. हिमांशु गुप्ता ने पुनः सरगुजा जिले के कैंसर मरीजों की सेवा हेतु सहमति प्रदान की है। इसे जिले के स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वर्तमान में डॉ. हिमांशु गुप्ता की पदस्थापना जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में की गई है।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सचिदानंद आ.स्व. रामगहन राम,उम्र- 57 वर्ष,निवासी मायापुर,गुरूद्वारा वार्ड, था0तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक एवं अनावेदकगण आत्मा राम आ.स्व. रामगहन राम व अन्य 01 के पिता स्व. रामगहन राम आ.स्व. शिवदास राम के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, मोहल्ला- मायापुर स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1469/1, 1470/2 रकबा क्रमशः 0.04, 0.01 हे0 खुली भूमि है। भूधारक रामगहन की मृत्यु दिनांक 31.05. 2024 को हो गई है। अतः भूधारक की मृत्यु हो जाने उपरांत उक्त आवेदित भूखण्ड से उनका नाम विलोपित कर स्वयं के नाम से आवेदित भूमि का फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा मृतक भूधारक रामगहन के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 29/05/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15/05/2026 को मेरे न्यायलयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय लिंक कोर्ट देवनगर तहसील
रामानुजनगर,जिला सूरजपुर,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./ब 121 /2021-22-2026

ग्राम देवनगर के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका परमिला आ0 रामनाथ जाति धोबी निवासी ग्राम देवनगर लिंक कोर्ट देवनगर तहसील रामानुजनगर जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदक/आवेदिका अपने भाई स्व0 रामनाथ का विलम्ब मृत्यू प्रमाण पत्र पंजीयन कराने बावत् अनुलब्धता प्रमाण पत्र मय अन्य सहायक दास्तावेज के साथ न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया है। मृत्यु दिनांक 02/01/2018

अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वम । अथवा किसी विविध प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 02/06/2026 को न्यायालयीन समयवधि में उपस्थित कर दावा/आपत्ति पेश कर सकतें है । उसके पयचात दावा आपत्ति में कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 19/05/2026 को न्यायलीन पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया ।

सील

नायब तहसीलदार
देवनगर
लिंक कोर्ट देवनगर

टीकाकरण अभियान के तहत बालिकाओं का किया गया निःशुल्क टीकाकरण

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 मई 2026 (घटती-घटना)। एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत जिले में कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. एस. मार्को के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा बालिकाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवापारा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियान के तहत केंद्र में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहां प्रतिदिन एचपीवी टीकाकरण किया जा रहा है, अब तक 7 बालिकाओं का सफल टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर अभिभावकों एवं किशोरियों को एचपीवी टीकाकरण के प्रति जागरूक भी

किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यह टीका विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर (बच्चेदानी के मुँह का कैंसर) से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। उन्होंने जिले के सभी पात्र बालिकाओं, अभिभावकों एवं नागरिकों से अपील किया है कि वे पात्र बालिकाओं (जिन किशोरियों ने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लेकिन 15 वर्ष का जन्मदिन न मनाया हो) का एचपीवी का टीकाकरण कराएं। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित है। एचपीवी टीका राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत मेडिकल कालेज संबद्ध जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी केमिस्ट हड़ताल के संबंध में आमजन हेतु आवश्यक सूचना

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,19 मई 2026 (घटती-घटना)। ऑनलाइन औषधियों की बिक्री के विरोध स्वरूप जिला औषधि विक्रेता संघ सरगुजा द्वारा दिनांक 20 मई 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य में आम नागरिकों को आवश्यक औषधियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस हेतु जिले में संचालित समस्त जनऔषधि केन्द्रों, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स,शासकीय चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स, अपोलो फार्मेसी यूनिट एवं अन्य औषधि वितरण केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं,ताकि आमजन एवं मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

दैनिक घटती-घटना की खबर का बड़ा असर

खबर प्रकाशित होते ही हरकत में आया पीएचई विभाग,रावतसरई पहुंचा अमला

चार में से दो बोर निकले सूखे,शेष दो में तत्काल हैंडपंप लगाकर बहाल की गई पेयजल सुविधा

-राजन पाण्डेय-

बैकुंठपुर/कोरिया,19 मई 2026 (घटती-घटना)।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत को लेकर दैनिक घटती घटना द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित खबर सुशासन का सूखा उत्सव कागजों में दौड़ रहा जल जीवन मिशन,ज़मीन पर बूंद-बूंद को तरसती जनता का बड़ा असर सामने आया है, खबर प्रकाशित होते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग हरकत में आ गया और विभागीय अमला तत्काल ग्राम पंचायत रावतसरई पहुंचकर मौके का निरीक्षण करने लगा। बता दे की लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहे ग्राम सिंहपानी और आसपास के ग्रामीणों के लिए यह कार्रवाई राहत लेकर आई है, निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने क्षेत्र में पूर्व में कराए गए बोरों की जांच की, जिसमें सामने आया कि कुल चार बोरों में से दो पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि दो बोरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, इसके बाद विभाग ने तत्काल निर्णय लेते हुए दोनों चालू बोरों में हैंडपंप स्थापित कर पेयजल सुविधा बहाल कर दी, ग्रामीणों का कहना है कि महीनों से गांव में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई थी, गर्मी बढ़ने के साथ हालात और खराब हो गए थे। महिलाएं और बच्चे सुबह-शाम कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर थे, गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और अन्य व्यवस्थाओं के दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था।

खबर के बाद प्रशासन की बढ़ी सक्रियता

दैनिक घटती घटना में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल बढ़ गई,ग्रामीणों के अनुसार लंबे समय से शिकायतें और आवेदन दिए जा रहे थे,लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हो रही थी। जैसे ही मामला मीडिया में प्रमुखता से सामने आया, विभाग ने तत्काल टीम गठित कर गांव भेजी,पीएचई विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की और पेयजल स्रोतों का निरीक्षण किया, जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जिन चार बोरों के भरोसे गांव की पेयजल व्यवस्था थी,उनमें से दो पूरी तरह सूखे पड़े हैं, शेष दो बोरों में पानी उपलब्ध होने के बावजूद हैंडपंप नहीं लगाए गए थे, जिसके कारण ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, विभागीय इंजीनियरों और कर्मचारियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों उपयोग योग्य बोरों में हैंडपंप स्थापित कराया। हैंडपंप शुरू होते ही ग्रामीणों के चेहरों पर राहत दिखाई दी।

कागजों में योजनाएं,जमीन पर संकट

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में कई योजनाओं की घोषणाएं तो हुई,लेकिन उनका लाभ लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, गांव में पाइपलाइन,जलस्रोत और पेयजल व्यवस्था को लेकर कई दावे किए गए,लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी, गांव की महिलाओं ने बताया कि कई बार अधिकारियों को समस्या बताई गई,लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला,गर्मी के दिनों में हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों को निजी साधनों और दूरस्थ स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा था,ग्रामीणों का कहना है कि यदि मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाता तो शायद समस्या का समाधान और लंबा खिंच जाता। लोगों ने कहा कि समाचार प्रकाशित होने के बाद ही विभाग की नींद खुली और तत्काल कार्रवाई देखने को मिली।

पंचायत प्रतिनिधियों ने जताया आभार

पंच संघ अध्यक्ष प्रेम सागर तिवारी सहित ग्राम पंचायत के पंचों और जनप्रतिनिधियों ने दैनिक घटती घटना और विभागीय टीम के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने गांव की वास्तविक समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,प्रेम सागर तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाना चाहिए,उन्होंने कहा कि जब तक गांवों में पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत नहीं होंगी, तब तक विकास के दावे अधूरे रहेंगे,उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएचई विभाग आगे भी इसी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम करेगा तथा शेष समस्याओं का भी जल्द समाधान करेगा।

जवाबदेही का बना उदाहरण

रावतसरई की यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि जब मीडिया जनसमस्याओं को मजबूती से उठाता है तो प्रशासन को जवाबदेह बनना पड़ता है,ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो फाइलों और योजनाओं के बीच दबकर रह जाती हैं,लेकिन जब जनता की आवाज खबर बनती है,तो उसका असर जमीन पर दिखाई देता है,रावतसरई में हैंडपंप स्थापना की यह कार्रवाई सिर्फ पेयजल सुविधा बहाल होने की खबर नहीं, बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि सजग पत्रकारिता और जनदबाव प्रशासनिक व्यवस्था को सक्रिय करने की ताकत रखते हैं।

भीषण गर्मी में बड़ी राहत

भीषण गर्मी के बीच हैंडपंप शुरू होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को दूर-दूर जाकर पानी लाने की मजबूरी से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है, महिलाओं ने कहा कि अब समय और श्रम दोनों की बचत होगी,हालांकि ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि जो दो बोर पूरी तरह सूखे पाए गए हैं,उनकी जगह नए बोर कराए जाएं ताकि भविष्य में फिर से पेयजल संकट उत्पन्न न हो। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई गई है, ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्थायी पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता है,क्योंकि हर गर्मी में पानी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है, यदि समय रहते व्यापक योजना नहीं बनाई गई तो आने वाले वर्षों में संकट और गहरा सकता है।

मीडिया बना जनता की आवाज

ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने दैनिक घटती-घटना को धन्यवाद देते हुए कहा कि समाचार पत्र ने सिर्फ खबर प्रकाशित नहीं की, बल्कि गांव की पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया, लोगों ने कहा कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद जब समाधान नहीं हुआ, तब मीडिया ने मुद्दे को मजबूती से उठाया और प्रशासन को जवाबदेह बनने पर मजबूर किया,ग्रामीणों ने विभागीय इंजीनियर भूपेंद्र कोर्चे, पंचायत प्रतिनिधियों और पंच संघ अध्यक्ष प्रेमसागर तिवारी का भी आभार व्यक्त किया। लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी दैनिक घटती घटना जनहित से जुड़े मुद्दों को इसी तरह प्रमुखता से उठाता रहेगा ताकि प्रशासनिक तंत्र सक्रिय बना रहे और आम जनता को समय पर राहत मिल सके।

सुशासन तिहार में छाया 'ट्रैफिक पाठशाला' का जादू

महेश मिश्रा के एजुकेशनल स्टाल ने जीता लोगों का दिल,सड़क सुरक्षा के सिखाए जीवनरक्षक गुर

-संवाददाता-

सोनहत,19 मई 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम पोड़ी में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में जहां शासन की विभिन्न योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही थी,वहीं यातायात विभाग का एक अनोखा और जागरूकता से भरपूर स्टाल पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण बन गया,अपनी अलग कार्यशैली और सड़क सुरक्षा के प्रति लगातार सक्रियता के लिए पहचाने जाने वाले यातायात विभाग के महेश मिश्रा द्वारा लगाए गए इस ट्रैफिक पाठशाला स्टाल ने लोगों का ध्यान तो खींचा ही, साथ ही ग्रामीणों और युवाओं को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों की व्यावहारिक जानकारी भी दी, शिविर में पहुंचे लोगों की भीड़ लगातार इस स्टाल की ओर उमड़ती रही, कोई हेलमेट के महत्व को समझ रहा था तो कोई दुर्घटना के बाद मिलने वाली सरकारी सहायता की जानकारी ले रहा था, कई ग्रामीणों ने पहली बार सड़क सुरक्षा से जुड़े ऐसे पहलुओं को जाना, जिनकी जानकारी अब तक उन्हें नहीं थी।

इस दौरान यातायात विभाग के महेश मिश्रा के साथ सोनहत थाना प्रभारी विनोद पासवान और एसआई राठिया भी पूरी सक्रियता के साथ मौजूद रहे,पुलिस टीम ने शिविर में आए ग्रामीणों, युवाओं और वाहन चालकों से सीधे संवाद कर उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया,महेश मिश्रा ने बेहद सरल और व्यवहारिक तरीके से लोगों को समझाया कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए जरूरी है,उन्होंने सीट बेल्ट की अनिवार्यता और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग से होने वाले खतरों पर भी विस्तार से जानकारी दी,उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही किस तरह बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है।

सुशासन तिहार में बना आकर्षण का केंद्र

पूरे शिविर के दौरान यातायात विभाग का यह स्टाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर वर्ग के लोगों ने यहां पहुंचकर जानकारी ली,इस पहल ने यह साबित कर दिया कि यदि पुलिस और प्रशासन केवल कार्रवाई तक सीमित न रहकर जागरूकता को प्राथमिकता दें,तो समाज में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

हिट एंड रन और मुआवजे की जानकारी ने बढ़ाई जागरूकता

स्टाल के माध्यम से लोगों को सड़क संकेतों की पहचान, गति सीमा का पालन और दुर्घटना के दौरान चोटों से बचने के तकनीकी उपायों की भी जानकारी दी गई। विशेष रूप से शासन द्वारा हिट एंड रन मामलों और मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए बनाए गए मुआवजा प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया, ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पहली बार यह जानकारी मिली कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में शासन द्वारा आर्थिक सहायता और कानूनी सुरक्षा के क्या प्रावधान मौजूद हैं, कई लोगों ने मौके पर ही सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाएं दूर कीं और पुलिस टीम ने भी बेहद सहजता से हर प्रश्न का जवाब दिया।

पुलिस का कम सिर्फ चालान नहीं,जीवन बचाने भी है... बना बड़ा संदेश

यातायात विभाग के इस एजुकेशनल स्टाल ने लोगों के बीच पुलिस की एक सकारात्मक और संवेदनशील छवि प्रस्तुत की, आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस को केवल चालान और कार्रवाई से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस पहल ने यह संदेश दिया कि पुलिस का असली उद्देश्य लोगों की जान बचाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है,स्टाल में मौजूद लोगों ने कहा कि यदि इस तरह की जागरूकता मुहिम गांव-गांव तक पहुंचे तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है।

महेश मिश्रा के प्रयासों की हुई जमकर सराहना

शिविर में उपस्थित ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने महेश मिश्रा की इस पहल की खुलकर सराहना की, लोगों का कहना था कि सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को जिस सहज और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत किया गया,वह वास्तव में प्रभावी और प्रेरणादायक था, स्थानीय ग्रामीण राम कुमार ने कहा आज के दौर में सड़क सुरक्षा की ऐसी बारीकियां कम ही देखने को मिलती हैं, महेश मिश्रा ने जिस तरह हेलमेट और हिट एंड रन के नियम समझाए, उससे हमारे जैसे ग्रामीणों का डर दूर हुआ है। अब हमें पता है कि दुर्घटना के समय शासन से क्या मदद मिल सकती है।

CMYK

छत्तीसगढ़ में फार्मेसी शिक्षा का विस्फोट,डिग्रियों के ढेर पर बेरोजगारी का संकट

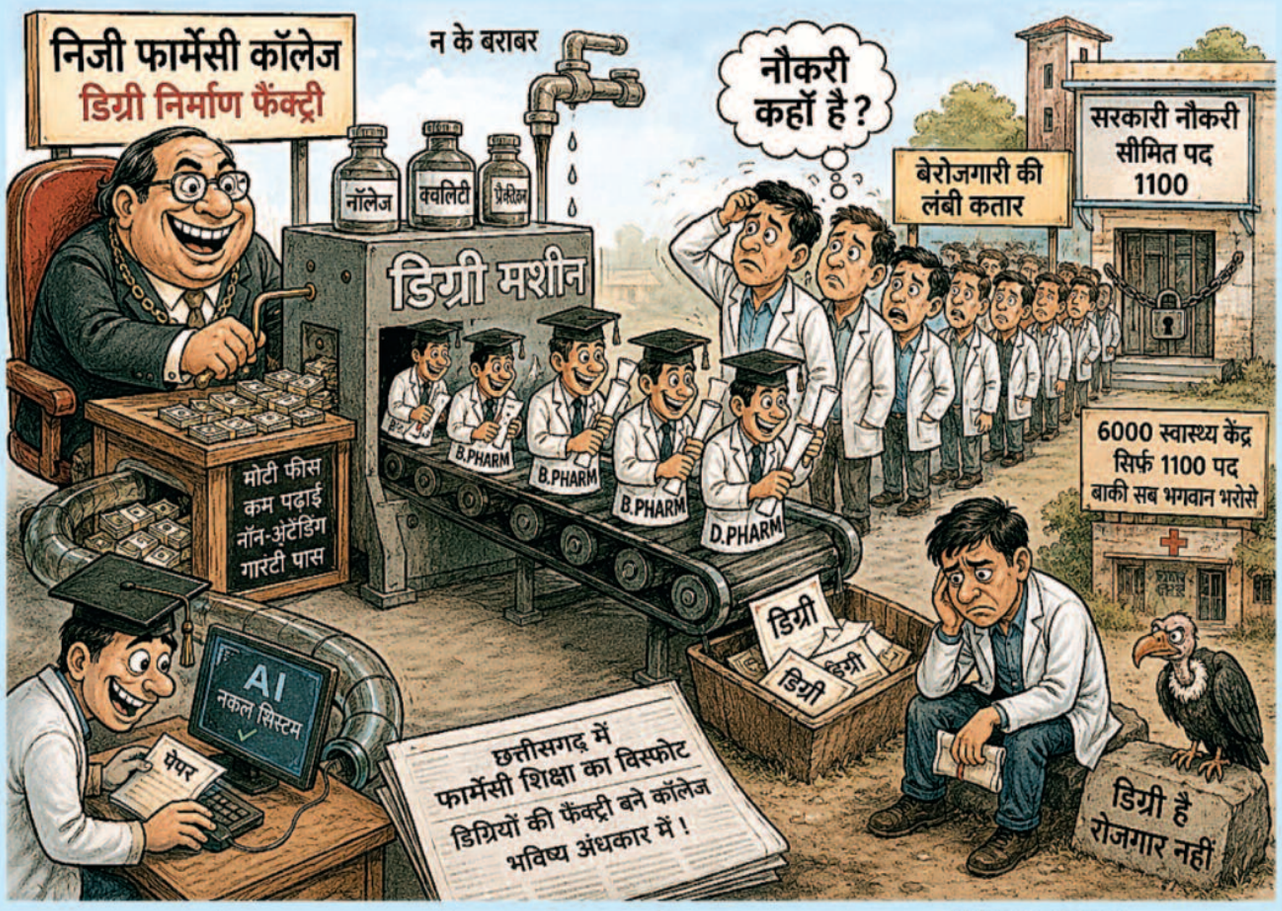

100 निजी कॉलेज,लेकिन नौकरी नहीं,फार्मेसी छात्रों का भविष्य अधर में...

फार्मेसी शिक्षा या डिग्री कारोबार? छत्तीसगढ़ में बढ़ते निजी कॉलेजों पर उठे सवाल

नॉन-अटेंडिंग से निकल रहे फार्मासिस्ट! प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर मंडराया खतरा

हर साल 7 हजार नए फार्मासिस्ट,लेकिन रोजगार के नाम पर सन्नाटा

फार्मेसी कॉलेजों की बाढ़,रोजगार का अकाल- युवा पूछ रहे...डिग्री लेकर जाएं कहाँ?

फार्मा शिक्षा की 'फैक्ट्री' बनता छत्तीसगढ़,गुणवत्ता और रोजगार दोनों संकट में...

दवा से जुड़ी पढ़ाई पर सवाल,बिना क्लास,बिना प्रैक्टिकल बन रहे फार्मासिस्ट!

फार्मेसी डिग्री का बढ़ता बाजार,लेकिन सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद

स्वास्थ्य व्यवस्था से खिलवाड़? फार्मेसी शिक्षा में नकल,नॉन-अटेंडिंग और बेरोजगारी का खेल

प्रदेश में फार्मासिस्टों की फौज तैयार,लेकिन रोजगार नीति गायब

फार्मेसी शिक्षा की अंधाधुंध मंजूरी पर सवाल,युवाओं का भविष्य संकट में...

-न्यूज डेस्क-

रायपुर/अंबिकापुर/कोरिया,19 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में फार्मेसी शिक्षा आज ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है,जहां डिग्रियों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है,लेकिन रोजगार,गुणवत्ता और भविष्य लगातार सिकुड़ता जा रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के भीतर निजी फार्मेसी कॉलेजों की संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ी है,आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 100 निजी फार्मेसी संस्थान संचालित हो रहे हैं, जबकि शासकीय स्तर पर स्वतंत्र फार्मेसी कॉलेजों की संख्या बेहद सीमित है।

हालांकि रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,गहिरागुरु विश्वविद्यालय तथा शासकीय पॉलिटेक्निक रायपुर में फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित हैं, लेकिन राज्य में अब तक स्वतंत्र और व्यापक स्तर पर सरकारी फार्मेसी शिक्षा व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है, इसी बीच निजी कॉलेजों की बढ़ती संख्या ने शिक्षा व्यवस्था को व्यवसाय मॉडल में बदलने के आरोपों को जन्म दिया है, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते इस क्षेत्र में नियंत्रण और सुधार नहीं किए गए, तो आने वाले वर्षों में हजारों फार्मेसी स्नातक बेरोजगारी, आर्थिक शोषण और मानसिक तनाव का सामना करने को मजबूर होंगे।

शिक्षा या सिर्फ डिग्री वितरण?

फार्मेसी शिक्षा मूल रूप से मानव स्वास्थ्य से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, एक प्रशिक्षित फार्मासिस्ट केवल दवा विक्रेता नहीं होता, बल्कि मरीज तक सही दवा,सही मात्रा और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन प्रदेश के कई निजी कॉलेजों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वहां नियमित पढ़ाई और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के बजाय डिग्री वितरण मॉडल हावी हो चुका है।

'नॉन-अटेंडिंग' संस्कृति ने बढ़ाई चिंता

प्रदेश के कई निजी संस्थानों में नॉन-अटेंडिंग व्यवस्था की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं, आरोप हैं कि छात्रों से मोटी फीस लेकर उन्हें नियमित कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना परीक्षा में बैठने की सुविधा दी जा रही है, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि कई छात्र कॉलेज परिसर तक पहुंचे बिना डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर रहे हैं, हाल के वर्षों में तकनीकी माध्यमों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से सामूहिक नकल और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों की चर्चाओं ने भी फार्मेसी शिक्षा की साख पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है, विशेषज्ञों के अनुसार यदि बिना प्रैक्टिकल ज्ञान और कौशल के छात्र डिग्री लेकर निकलेंगे, तो इसका सीधा खतरा मरीजों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा।

हर साल 7 हजार नए फार्मासिस्ट, लेकिन रोजगार के अवसर सीमित

प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 40 हजार पंजीकृत फार्मासिस्ट बताए जा रहे हैं, दूसरी ओर निजी कॉलेजों से हर वर्ष करीब 7 हजार नए छात्र फार्मेसी की डिग्री लेकर बाहर निकल रहे हैं,यदि यही स्थिति बनी रही,तो अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में पंजीकृत फार्मासिस्टों की संख्या 80 हजार से लेकर 1 लाख तक पहुंच सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा कहां? आज अधिकांश छात्र फार्मेसी को रोजगार और मेडिकल स्टोर लाइसेंस प्राप्त करने के माध्यम के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टोरों की संख्या भी तेजी से बढ़ने के कारण प्रतिस्पर्धा तीव्र हो चुकी है, छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई मेडिकल स्टोर सीमित आय के कारण टिक नहीं पा रहे।

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में भी गंभीर कमी, 6000 स्वास्थ्य केंद्र,लेकिन सिर्फ 1100 पद

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 6000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं, लेकिन इनके मुकाबले केवल लगभग 1100 फार्मासिस्ट पद ही स्वीकृत हैं, स्थिति यह है कि अनेक स्वास्थ्य केंद्र बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे हैं, कई जगह दवा वितरण और औषधीय निगरानी की जिम्मेदारी अन्य कर्मचारियों के भरोसे चल रही है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल रोजगार का नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य सुरक्षा का भी गंभीर मुद्दा है।

वर्षों से खाली पड़े तकनीकी पद

सीजीएमसी, शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और अन्य तकनीकी विभागों में भी लंबे समय से फार्मासिस्टों एवं फार्मा अधिकारियों के पद रिक्त बताए जा रहे हैं, युवाओं का आरोप है कि सरकार एक ओर निजी कॉलेजों को अनुमति दे रही है, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन और भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर पहल नहीं कर रही, कई युवाओं का कहना है कि वे वर्षों तक पढ़ाई करने और लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी नौकरी के लिए भटकने को मजबूर हैं।

ब्लड बैंक और वेटनरी अस्पतालों में भी अवसर की मांग...

फार्मा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश के शासकीय और निजी ब्लड बैंकों में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की नियुक्ति अनिवार्य की जानी चाहिए, इसी तरह वेटनरी अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट पद सृजित करने की मांग लगातार उठ रही है, विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, डोज प्रबंधन और औषधीय सलाह जैसे कार्यों में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।

फार्मासिस्ट संगठनों की प्रमुख मांगें

1. निजी कॉलेजों की सख्त जांच- फर्जी उपस्थिति,नॉन-अटेंडिंग व्यवस्था,सामूहिक नकल और शैक्षणिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है...

2. शासकीय फार्मेसी कॉलेज स्थापित हों- प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती फार्मेसी शिक्षा के लिए नए स्वतंत्र शासकीय फार्मेसी कॉलेज खोलने की मांग तेज हो रही है...

3. रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती- स्वास्थ्य केंद्रों,ब्लड बैंकों,औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और वेटनरी अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने की मांग उठ रही है...

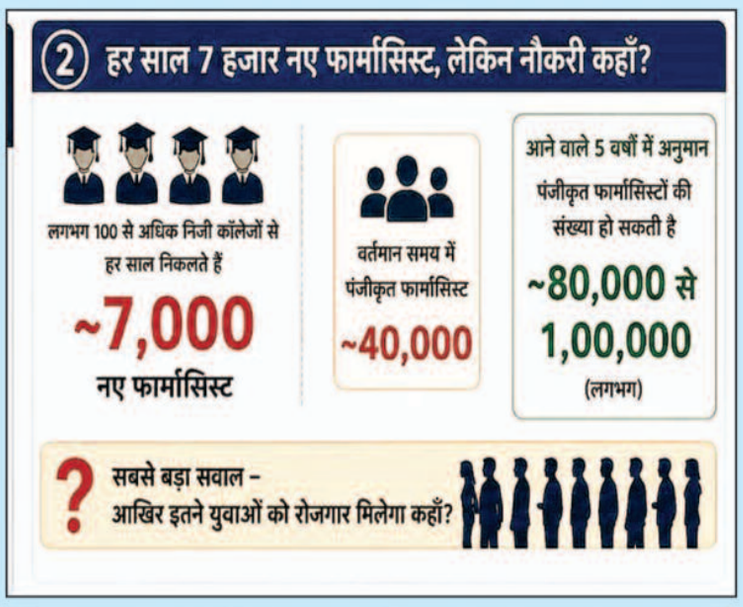

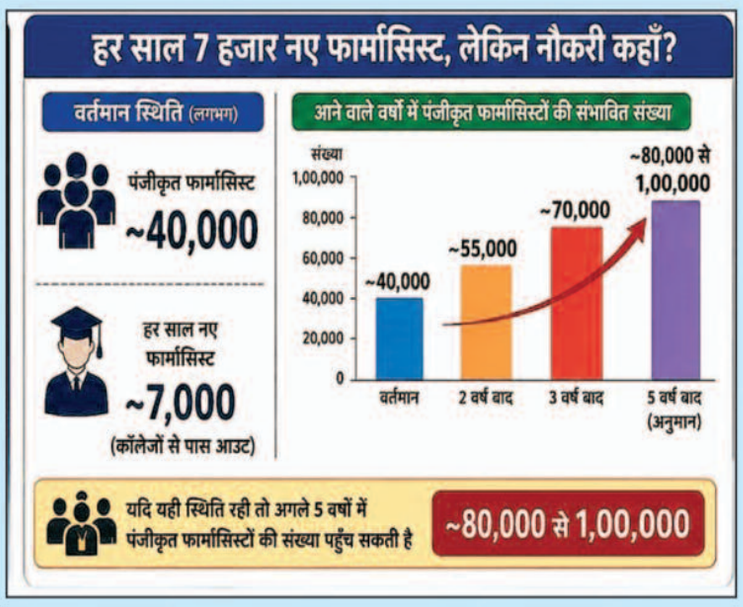

सरकार को फार्मा सेक्टर विकसित करना होगा : हीरा शंकर साहू

पूर्व निर्वाचित सदस्य छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल हीरा शंकर साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में फार्मेसी और फार्मासिस्टों की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है,उन्होंने कहा कि लगातार डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राएं रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और फार्मेसी की डिग्री अब केवल मेडिकल स्टोर खोलने तक सीमित होती जा रही है, उनके अनुसार सरकार को नए रोजगार सृजन के लिए फार्मा सेक्टर को विकसित करना होगा। बड़ी दवा कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए मूलभूत सुविधाएं और प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके।

नॉन-अटेंडिंग कॉलेजों की न्यायालयीन जांच हो : राहुल वर्मा

इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश सचिव राहुल वर्मा ने कहा कि फार्मासिस्ट सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ा प्रोफेशन है,उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद मेडिकल स्टोर खोलने की होड़ में फार्मेसी शिक्षा की ओर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है,कई लोग केवल लाइसेंस और मेडिकल स्टोर के उद्देश्य से डी.फार्म कोर्स कर रहे हैं, राहुल वर्मा ने आरोप लगाया कि शॉर्टकट डिग्री लेने के लिए कई छात्र नॉन-अटेंडिंग कोर्स का सहारा ले रहे हैं,उन्होंने कहा कि ऐसे निजी कॉलेजों की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने के लिए इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन जनहित याचिका दायर करेगा।

बड़ा सवाल... क्या सरकार समय रहते जागेगी?

छत्तीसगढ़ में फार्मेसी शिक्षा का यह तेजी से फैलता ढांचा अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है,क्या शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता आधारित बनाया जाएगा? क्या रोजगार सृजन की दिशा में ठोस नीति बनेगी? क्या निजी कॉलेजों की जवाबदेही तय होगी? और सबसे महत्वपूर्ण – क्या हजारों युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सकेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन एक बात साफ है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो फार्मेसी शिक्षा का यह अनियंत्रित विस्तार आने वाले वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य – दोनों क्षेत्रों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

CMYK

दिशा पाटनी भी ग्लोबल मंच पर बना रही पहचान

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा,दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के बाद बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री दिशा पाटनी भी ग्लोबल मंच पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही हैं। दिशा पाटनी की पहली इंटरनेशनल फिल्म 'द पोर्टल ऑफ फोर्स' का ट्रेलर रिलीज हो गया है,जिसने काफी चर्चा बटोर ली है। यह फिल्म एक काल्पनिक और रहस्यमयी दुनिया की कहानी पर आधारित है। 'स्टेटिगार्ड्स वर्सेज होलीगार्ड्स' नाम की नई फिल्म सीरीज की यह पहली कड़ी है। फिल्म की कहानी लाडो ओखोटनिकोव ने तैयार की है। इसमें दो प्राचीन शक्तियों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। एक पक्ष दुनिया में संतुलन और नियम बनाए रखने की बात करता है, जबकि दूसरा पक्ष अलग विचारधारा और नई दिशा का समर्थन करता है। इसी टकराव के बीच दिशा पाटनी का किरदार जेसिका सबसे अहम भूमिका में नजर आता है। फिल्म में जेसिका को एक ऐसी युवती के रूप में दिखाया गया है, जिसका संबंध दोनों विरोधी गुटों से है। वह दोनों पक्षों के नेताओं की बेटी है और इसी वजह से उसे दो दुनियाओं के बीच एक मजबूत कड़ी माना जाता है। कहानी में दुनिया का भविष्य उसके फैसलों पर निर्भर करता दिखाई देता है। ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि जेसिका अपनी रहस्यमयी शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। उसके सामने सिर्फ दुश्मनों से लड़ने की चुनौती नहीं है,बल्कि अपनी असली पहचान खोजने और सही रास्ता चुनने की जिम्मेदारी भी है। ट्रेलर में दिशा पाटनी के कई दमदार एक्शन दृश्य देखने को मिलते हैं। वह तलवारबाजी से लेकर रहस्यमयी शक्तियों का इस्तेमाल करती नजर आती हैं। उनके एक्शन सीक्वेंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा है। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी मजबूत मानी जा रही है। दिशा पाटनी के साथ हॉलीवुड अभिनेता केविन स्पेसी, डॉल्फ लुंडग्रेन और टायरेस गिब्सन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। दिशा पाटनी ने फिल्म को लेकर उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि पहली इंटरनेशनल फिल्म में काम करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि अलग-अलग देशों के कलाकारों के साथ काम करते हुए उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।

इंस्पेक्टर अविनाश में आंतरिक भावनाओं की जरूरत : उर्वशी रौतेला

वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के नए सीजन में पूनम मिश्रा के दमदार किरदार में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला पुनः वापसी कर रही हैं। उर्वशी ने अपने किरदार और अभिनय के दृष्टिकोण को लेकर कुछ बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उनकी सार्वजनिक छवि हमेशा ग्लैमर और बाहरी सुंदरता से जुड़ी रही है, लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश जैसे प्रोजेक्ट्स में दिखावे और चमक-धमक से कहीं अधिक सच्ची और आंतरिक भावनाओं की जरूरत होती है। मीडिया से चर्चा में उर्वशी ने खुलासा किया कि एक कलाकार के रूप में वास्तविक रूप से आगे बढ़ने और अपने काम को निखारने के लिए परफॉर्मेंस वैनिटी यानी हर फ्रेम में एकदम परफेक्ट और खूबसूरत दिखने की सोच को त्यागना बेहद आवश्यक होता है। उन्होंने स्पष्ट किया,लोग अक्सर मुझसे हर फ्रेम, हर अभिव्यक्ति और हर पल में परफेक्शन की उम्मीद करते हैं,क्योंकि मेरी छवि वर्षों से ग्लैमरस रही है। लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश जैसे गंभीर और यथार्थवादी प्रोजेक्ट विजुअल परफेक्शन से ज्यादा भावनात्मक ईमानदारी और सच्चाई की मांग करते हैं। अभिनेत्री ने बताया कि पूनम मिश्रा के इस किरदार को निभाने के लिए, उन्होंने खुद को वर्तमान क्षण में अधिक प्रेजेंट रखने पर ध्यान केंद्रित किया। उर्वशी ने कहा, असल जिंदगी में जब लोग किसी मुश्किल या दर्दनाक हालात से गुजर रहे होते हैं, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कैसे दिख रहे हैं। वे केवल उस स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं,उन हालातों से जूझ रहे होते हैं, और अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस कर रहे होते हैं। एक अभिनेता के तौर पर इस सच्चाई को समझना और उसे अपनी प्रस्तुति में उतारना मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उर्वशी ने यह भी बताया कि संयमित अभिनय,यानी कम शब्दों,शांत शारीरिक भाषा और नियंत्रित भावों के जरिए गहरी भावनाएं व्यक्त करना, अक्सर अधिक नाटकीय अभिनय से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, मौन, स्थिरता और नियंत्रित भावनाएं दिखाने के लिए एक अलग तरह के आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। कई बार, अपनी भावनाओं को कम करके या दबी हुई स्थिति में सच दिखाना, अति-नाटकीय प्रदर्शन से भी अधिक चुनौतीपूर्ण होता है और उसका प्रभाव भी गहरा होता है। उर्वशी ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि, एक कलाकार के तौर पर, यह उनके लिए यकीनन आजादी देने वाला अनुभव था, क्योंकि इसने मुझे हर पल अपनी छवि बनाए रखने के दबाव के बिना, अपनी भावनाओं को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दिखाने का मौका दिया। यह उनके अभिनय करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है,जहां वे अपनी ग्लैमरस छवि से हटकर, अधिक गंभीर और संवेदनशील किरदारों में अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि इंस्पेक्टर अविनाश पहली बार साल 2023 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से खूब सराहना मिली थी। इस सीरीज में रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में हैं।

एक्टर को खाने से मना किया तो निर्माता पर भड़क उठे अक्षय खन्ना

बॉलीवुड के सबसे गंभीर और खामोश मिजाज अभिनेताओं में शुमार अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की सफलता का आनंद ले रहे हैं। दिग्गज अभिनेता अमित बहल ने एक साक्षात्कार में अक्षय खन्ना से जुड़ा एक बेहद भावुक और प्रेरक किस्सा साझा किया। बहल के मुताबिक, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ काम कर रहे एक चरित्र अभिनेता लंच के लिए उस होटल में आए थे जहाँ अक्षय रुके हुए थे। वह कलाकार किसी अन्य होटल में ठहरे थे। जैसे ही उन्होंने भोजन का पहला निवाला उठाना चाहा, प्रोडक्शन टीम के एक सदस्य ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि जो कलाकार इस होटल में नहीं रुका है, वह यहाँ का खाना नहीं खा सकता। बताया जाता है कि यह आपत्ति निर्माता की पत्नी या किसी करीबी रिश्तेदार की ओर से आई थी। अपमानित महसूस कर रहे उस कलाकार ने चुपचाप अपनी प्लेट रख दी और किनारे जाकर बैठ गए। अक्षय खन्ना दूर खड़े यह सब देख रहे थे। आमतौर पर सेट पर अपने काम से काम रखने वाले और बेहद शांत रहने वाले अक्षय का गुस्सा उस दिन ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वे तुरंत बीच-बचाव में आए और पूरी यूनिट के सामने भूख और इंसानियत पर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। अमित बहल ने बताया कि अक्षय उस दिन भारी गुस्से में थे। उन्होंने निर्माता और क्रू मेंबर्स को आड़े हाथों लेते हुए खरी-खोटी सुनाई। अक्षय ने गरजते हुए कहा कि कोई भी फिल्म इस बात से सफल नहीं होती कि आपने कितनी प्लेटें बचाईं या राशन का कितना हिसाब रखा, बल्कि फिल्म लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूख का अपमान करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। अक्षय का यह निर्भीक और मानवीय पक्ष देखकर सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान था। यह वाकया साबित करता है कि पर्दे पर नकारात्मक भूमिकाएं निभाने वाला यह कलाकार असल जिंदगी में सिद्धांतों और नैतिकता से कभी समझौता नहीं करता। बता दें कि फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के खूंखार विलेन के रूप में अक्षय खन्ना की अदाकारी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। लेकिन अभिनय की बारीकियों के अलावा अक्षय अपनी उस इंसानियत के लिए भी जाने जाते हैं, जिसकी झलक ग्लैमर की दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। हाल ही में उनके एक पुराने सहयोगी ने अक्षय खन्ना के उस रूप का खुलासा किया है, जब उन्होंने एक साथी कलाकार के सम्मान के लिए पूरी प्रोडक्शन टीम और निर्माता की क्लास लगा दी थी।

मातृत्व अनुभव को सांझा करते हुए रोने लगी कियारा आडवाणी

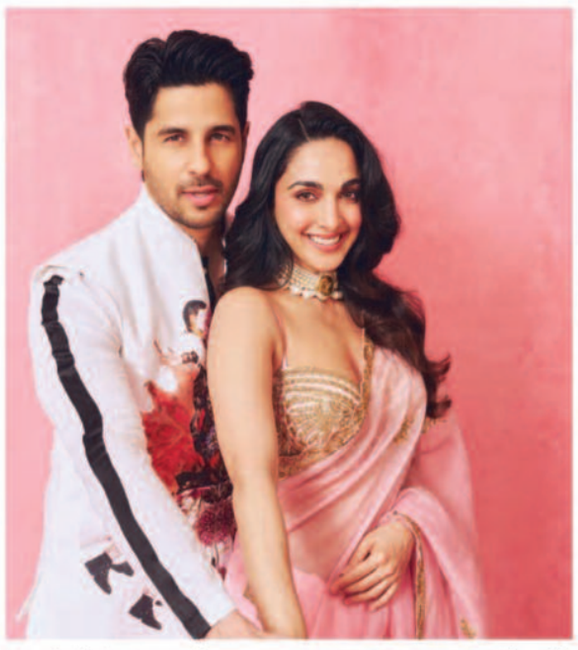

हाल ही में कियारा अपने मातृत्व अनुभव और पोस्टपार्टम के बाद के दौर पर खुलकर बात करने के लिए सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की,जहाँ उन्होंने मां बनने के बाद एक महिला के जीवन में आने वाले गहरे बदलावों को साझा किया। कियारा ने बताया कि ये बदलाव केवल शारीरिक ही नहीं,बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी होते हैं, जो एक महिला के पूरे अस्तित्व को नया आयाम देते हैं। यह मां बनने के बाद कियारा का पहला पॉडकास्ट था, जिसमें उन्होंने अपनी मदरहुड यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। इस पॉडकास्ट की एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कियारा इंटरव्यू के दौरान भावुक होकर रोने लगती हैं। अभिनेत्री ने कहा कि मां बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने मातृत्व को एक ऐसा अनुभव बताया जिसने उनकी सोच, भावनाओं और पहचान तक को नया आयाम दिया है। कियारा के अनुसार, यह सिर्फ एक भूमिका नहीं, बल्कि स्वयं को नए सिरे से परिभाषित करने का सफर है। अपने पोस्टपार्टम दौर को याद करते हुए, कियारा ने बताया, 'मां बनने के बाद जिंदगी बिल्कुल एक नई दुनिया जैसी हो जाती है।' उन्होंने साझा किया कि बेटी के जन्म के करीब छह महीने बाद उन्होंने पहली बार खुद के इमोशंस और मानसिक स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। कियारा ने स्वीकार किया कि वह अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देती आई थीं, लेकिन मातृत्व ने उन्हें खुद से फिर से जुड़ने और अपनी भावनाओं को गहराई से समझने का महत्वपूर्ण अवसर दिया है।

यह उनके लिए आत्म-खोज और व्यक्तिगत विकास का एक अनमोल समय साबित हुआ है। इस मुश्किल और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण समय में, अभिनेत्री ने अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा की अटूट मदद और समर्थन की भी सराहना की। कियारा ने बताया कि सिद्धार्थ अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद देर रात उनसे मिलने पहुंच जाते थे। बेटी के जन्म के बाद, वह अक्सर छोटी-छोटी बातों पर भावुक हो जाती थीं, तब सिद्धार्थ उन्हें हर रात ड्राइव पर ले जाते थे ताकि उनका मन हल्का हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि जब सिद्धार्थ अपनी फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त थे, तब कियारा का मन उनसे दूर नहीं लग रहा था।

फिल्म 'आखिरी सवाल' सिर्फ मनोरंजन नहीं : त्रिधा चौधरी

अपनी आगामी फिल्म 'आखिरी सवाल' को लेकर अभिनेत्री त्रिधा चौधरी और समीरा रेड्डी ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला सिनेमा है। त्रिधा चौधरी ने बताया कि फिल्म में उन्होंने 'सारा' नाम की एक छात्रा का किरदार निभाया है। उनके मुताबिक शैक्षणिक संस्थान केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते, बल्कि वहीं से भविष्य के नेता और विचार तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है और वह उस पर पूरा विश्वास रखता है। त्रिधा का मानना है कि सिनेमा समाज में संवाद पैदा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है और यह कलाकारों को अपनी बात कहने की आजादी देता है। उन्होंने कहा कि फिल्म का उद्देश्य किसी समाज या वर्ग को बांटना नहीं है, बल्कि लोगों को गंभीर मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित करना है। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि विचारधारा किसी भी इंसान के जीवन और फैसलों को किस तरह प्रभावित करती है। त्रिधा ने पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि सभी कलाकारों और तकनीकी सदस्यों ने इस विषय को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वहीं समीरा रेड्डी लंबे समय बाद इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिल्म में उन्होंने वामपंथी विचारधारा रखने वाली महिला 'डॉ. पल्लवी' का किरदार निभाया है। उनका पात्र समाज के भीतर मौजूद कई दबे सवालों को सामने लाता है।

खेल समाचार

सिंधु बीडब्ल्यूएफ के 15-अंक के नये प्रारुप को लेकर खुश नहीं

नई दिल्ली,19 मई 2026। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु अगले साल से लागू होने वाले विश्व बैडमिंटन महासंघ बैडमिंटन के नए 15-अंक के प्रारुप को लेकर उत्साहित नहीं हैं। सिंधु का मानना है कि ये थकानभरा और चुनौतीपूर्ण साबित होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु के अनुसार ये नया प्रारुप आक्रामक खिलाड़ियों के लिए ही लाभदायक रहेगा पर इससे खेल में शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि बीडब्ल्यूएफ ने हाल ही में 15 अंक वाले तीन गेम की स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है, इसे 4 जनवरी 2027 से लागू किया जाना है। इस घोषणा के बाद से ही खिलाड़ियों के ने इस नए प्रारूप को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सिंधु हाल ही में बीडब्ल्यूएफ 'एथलीट्स आयोग' की अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने पहले भी बताया है कि अधिकतर खिलाड़ी अब भी 21-अंक प्रणाली को बैडमिंटन के आकर्षण, लय और रणनीतिक गहराई के लिहाज से कही बेहतर मानते हैं। सिंधु ने ने नए स्कोरिंग प्रणाली पर विस्तार को लेकर कहा, 'हां, मुझे लगता है कि यह आक्रामक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है, लेकिन आपको शुरुआत से ही तेज होना होगा। आप शुरुआत में खुद को सेट नहीं कर सकते, तुरंत आक्रामक और तेज रहना होगा।' उन्होंने कहा, 'यह बहुत थकाऊ होगा और आपको हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। यह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला होगा क्योंकि आपको लगातार हर तरफ सक्रिय रहना होगा।' उनकी यह टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि खेल की गति और तीव्रता काफी बढ़ जाएगी, जिससे खिलाड़ियों पर लगातार दबाव बना रहेगा।

कोच फ्लेमिंग ने सीएसके की हार के लिए कप्तान रुतुराज को जिम्मेदार बताया

नई दिल्ली,19 मई 2026। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लीग मैच में मिली हार पर निराशा जतायी है। इस हार से सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं तकरीबन समाप्त हो गयी हैं। सीएसके को अब केवल एक मैच खेलना है। फ्लेमिंग ने हार के लिए कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि वह उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाये। बल्लेबाजी के दौरान वह रन नहीं बना पाये। उनकी कप्तानी भी अच्छी नहीं रही। सनराइजर्स के खिलाफ इस मैच में गायकवाड़ ने 21 गेंदों में केवल 15 रन बनाए। हैरानी की बात ये रही कि वह पारी शुरु करने के बाद भी एक भी चौका नहीं लगा पाये। किसी भी सलाकी बल्लेबाज से ऐसे प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जाती। वहीं उनके जोड़ीदार संजू सैमसन ने 13 गेंदों में तेजी से 27 रन बनाये। इस पूरे सत्र में गायकवाड़ का प्रदर्शन लगभग ऐसा ही रहा है, जिसमें निरंतरता और आक्रामक रवैये की कमी साफ दिख रही है। मैच के बाद फ्लेमिंग से जब रुतुराज ने कहा कि कप्तान से इस प्रकार के खेल की उम्मीद नहीं की जाती।

फुटबॉल वर्ल्डकप : ब्राजील और क्रोएशिया की टीमें घोषित

जूनियर नेमार की 3 साल बाद वापसी,स्पेन के लोपेज चोट के कारण बाहर

नई दिल्ली,19 मई 2026। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील और क्रोएशिया की टीमों का ऐलान हो गया है। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील में 3 साल बाद जूनियर नेमार की वापसी हुई है। क्रोएशिया ने 40 साल के लुका मोड्रिच को कप्तान बनाया है। वे अपना 5वां वर्ल्ड कप खेलेंगे। वहीं, स्पेन के युवा मिडफील्डर फर्मिन लोपेज दाएं पैर में फ्रैक्चर के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। जबकि, लैमिन यामल पहला मैच नहीं खेलेंगे। 48 टीमें के इस टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून से होगी। जोकि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में 16 शहरों में खेला जाएगा। हाल ही में फ्रांस और बेल्जियम ने भी अपनी-अपनी टीमों का ऐलान किया था।

चौथा वर्ल्ड कप खेलेंगे नेमार

ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी ने सोमवार को रियो डी जेनेरियो में टीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा- 'हमने पूरे साल नेमार का बारीकी से विश्लेषण किया। पिछले कुछ समय में उन्होंने लगातार फुटबॉल खेला है। उनकी फिटनेस इस बड़े मंच के लिए बिल्कुल दुरुस्त है।' 34 साल के नेमार चोट के कारण 2023 के बाद से ब्राजील के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए। वे करियर का चौथा वर्ल्ड कप (2014, 2018, 2022, 2026) खेलेंगे। ब्राजील को ग्रुप-सी में रखा गया है। उसका पहला मैच 13 जून को मोरक्को से होगा। फिर हैती और स्कॉटलैंड से मुकाबले होंगे। गोलकीपर एलिसन बेकर चोट से ठीक होकर लौटे हैं। रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर, बार्सिलोना के राफिन्हा और 19 साल के एंड्रिक फॉरवर्ड लाइन में होंगे। इस सीजन प्रीमियर लीग में चेल्सी के लिए 15 गोल और 5 असिस्ट करने वाले टॉप स्कोरर जोआओ पेड्रो को टीम में जगह नहीं मिली है।

मोड्रिच 200 इंटरनेशनल मैच पूरे कर सकते हैं...

क्रोएशिया के मुख्य कोच ज्लाटको डालिच ने 26 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। इसमें 40 साल के दिग्गज लुका मोड्रिच को चुना गया। वे करियर का 5वां वर्ल्ड कप खेलेंगे। वे पिछले महीने गाल की हड्डी टूटने की चोट का शिकार हो गए थे। डालिच ने उम्मीद जताई है कि वे 17 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वर्ल्ड कप मैच तक फिट हो जाएंगे। मोड्रिच 200 इंटरनेशनल मैच पूरे कर सकते हैं। टीम में स्टार फॉरवर्ड इवान पेरिसिच भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले तीनों वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के लिए गोल दागे हैं। क्रोएशिया की टीम 2018 वर्ल्ड कप की उपविजेता रही थी, जबकि 2022 वर्ल्ड कप में उसने तीसरा स्थान हासिल किया था। क्रोएशिया को ग्रुप-एल में रखा गया है। टीम 17 जून को इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। इसके बाद पनामा और घना से मुकाबले होंगे।

ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लोपेज बाहर

लैमिन यामल और फर्मिन लोपेज की चोट ने स्पेन की चिंता बढ़ा दी है। यामल चोट के कारण केप वर्डे 15 जून को होने वाले पहले मैच से बाहर हो गए हैं। जबकि 23 साल के मिडफील्डर लोपेज का वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट गया है। बार्सिलोना क्लब के अनुसार, रविवार को रियल बेटिस के खिलाफ स्पैनिश लीग मैच में लोपेज के दाएं पैर की 5वीं मेटाटार्सल हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। क्लब ने बताया कि उन्हें सर्जरी से गुजरना होगा और वे अगले महीने शुरू हो रहे वर्ल्ड कप तक फिट नहीं हो पाएंगे।

कई चीजों का त्याग करना होगा,शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है: सचिन तेंदुलकर

अहमदाबाद,19 मई 2026। भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का कहना है कि अगर माता-पिता अपने बच्चों को कामयाब होते देखना चाहते हैं, तो उन्हें आजादी देनी होगी। सचिन ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में खेलने के लिए त्याग करने होंगे,क्योंकि शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। सचिन अहमदाबाद में एसआरटी10 अल्टेवोल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के लॉन्च इवेंट में शामिल हुए, जिसमें आईसीसी चेयरमैन जय शाह और गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी पहुंचे। सचिन ने सभी माता-पिता को संदेश देते हुए कहा,'हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हों, और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। सबसे जरूरी यह है कि हमें अपने बच्चों को आजादी देनी चाहिए। आजादी और हौसला एक बेहतरीन मेल है, क्योंकि इसी से नतीजे मिलते हैं। मेरे माता-पिता ने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला। न ही मेरे भाई-बहनों ने मुझसे कभी पूछा कि मैं रन क्यों नहीं बना पा रहा हूं। जब मैंने दो क्लब या प्रैक्टिस मैच खेले, तो मैं पहले दो मैच में जीरो पर आउट हो गया और घर आ गया। तीसरे मैच में, मैंने एक रन बनाया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश था कि मैं कम से कम एक रन तो बना पाया। 'सचिन ने युवाओं से कहा कि वह जब भी मैदान पर जाएं, तो पूरी तैयारी के साथ जाएं।

महिला टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार : स्मृति मंधाना

मुंबई,19 मई 2026। अगले महीने इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होने वाले महिला टी-20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा है कि टीम की तैयारियां शानदार चल रही हैं और सभी खिलाड़ी बेहतरीन लय में नजर आ रही हैं। भारतीय टीम 12 देशों के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इससे पहले टीम बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले चुकी है और 22 मई को इंग्लैंड रवाना होगी, जहां मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी। मुंबई में महिला स्वच्छता ब्रांड के एक कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंधाना ने कहा कि टीम ने विश्व कप की तैयारियों में काफी मेहनत की है, हालांकि वह रणनीति को लेकर ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहतीं। उन्होंने कहा, 'कैंप बहुत अच्छा रहा। हम विश्व कप के लिए तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले एक सीरीज भी खेलेंगे। सभी खिलाड़ी अच्छी स्थिति में हैं और उन्होंने शानदार अभ्यास किया है। उम्मीद है कि हम इसी मेहनत को जारी रखेंगे, देश को गौरवान्वित करेंगे और ट्रॉफी भारत लेकर आएंगे।' कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत करते हुए मंधाना ने खेलों में करियर की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे खेल और खिलाड़ियों के संघर्ष को लेकर काफी जागरूक हैं। मंधाना ने कहा,'मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चों को यह संदेश मिले कि खेल और क्रिकेट में भी शानदार करियर बनाया जा सकता है। मैं हमेशा यही कहती हूं कि अपने जुनून को अपनाइए और पूरी प्रक्रिया का आनंद लीजिए।'

रायपुर में पेट्रोल 104.32 लीटर

डीजल भी महंगा...90 पैसे बढ़े दाम,4 दिन पहले 3-3 रुपए बढ़ाए थे,रसोई तक पड़ेगा असर

रायपुर,19 मई 2026। रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार फिर बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने फ्यूल के दाम करीब 90-90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल-डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। यानी सिर्फ 4 दिनों के भीतर दूसरी बार कीमतें बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। राजधानी में अब पेट्रोल की कीमत करीब 104.32 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल करीब 97.38 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रकों और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ने से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा खेती-किसानी में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने की लागत भी बढ़ेगी। वहीं बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी आने वाले दिनों में इजाफा देखने को मिल सकता है। इधर, रायगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने नियमों की अनदेखी और स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर मंगलवार देर रात खरसिया स्थित वंदना पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। इससे पहले कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों के बीच कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवाते नजर आए थे। कुछ स्थानों पर पंप बंद होने जैसी स्थिति भी बन गई थी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। हालांकि, अब स्थिति सामान्य है।

मुआवजे के लिए किसानों का सब्र टूटा

छत्तीसगढ़-यूपी बॉर्डर पर आज से महाजाम की तैयारी

रायपुर,19 मई 2026। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने वाला मुख्य मार्ग आज पूरी तरह ठप्प होने जा रहा है। पिछले दो दशकों से सरकारी उपेक्षा और प्रशासनिक संवेदनहीनता का दंश झेल रहे धनवार के ग्रामीणों के सब्र का बांध अब आखिरकार टूट चुका है। वर्ष 2005-06 में धनवार में आरटीओ परिसर के निर्माण के लिए प्रशासन ने 19 आदिवासी और किसान परिवारों की लगभग 20 एकड़ बेहद उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया था। उस वक्त किसानों को कई तरह के सरकारी दांव-पेच और सुनहरे वादों के जाल में फंसाया गया था। पूरे 20 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन पीड़ित प्रभावित परिवारों को मुआवजे का एक रुपया तक नसीब नहीं हो पाया है। व्यवस्था की इस घोर लापरवाही और तानाशाही के खिलाफ अब प्रभावित ग्रामीणों ने आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। आज सुबह 9:00 बजे से धनवार आरटीओ चेक पोस्ट के पास प्रभावित किसान अनिश्चितकालीन चक्का जाम और धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26 वीं बैठक

देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनेगा बस्तर...नक्सल उन्मूलन अभियान में कांग्रेस सरकार ने नहीं की मदद : शाह

जगदलपुर,19 मई 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26 वीं बैठक हुई, जिसमें विकास का रोडमैप तैयार किया गया। बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा...बस्तर में अब भय का माहौल समाप्त हो चुका है। हर जगह उत्साह,विश्वास नजर आ रहा है। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। कभी बंदूकों की साया में जीने वाला बस्तर आज चैन की सांस ले रहा है।

उन्होंने कहा,नक्सल उन्मूलन अभियान में ढेर सारी नॉन बीजेपी सरकारों ने हमारा सहयोग किया है,लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस (भूपेश) सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया। गृहमंत्री शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की चार महत्वपूर्ण तिथियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहली तारीख 13 दिसंबर 2023 थी,जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी,लेकिन कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में केंद्र का सहयोग नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख 24 अगस्त 2024 थी, जब सभी राज्यों के डीजीपी की बैठक में 'नक्सल मुक्त भारत' का संकल्प लिया गया। तीसरी तारीख 31 मार्च 2026 रही, जब देश से नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य तय किया गया। वहीं 19 मई 2026 को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास की नई परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया। बस्तर को अब देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा मौजूद थे। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद इसलिए पनपा क्योंकि इन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंचा, लेकिन विकास रुकने की सबसे बड़ी वजह भी नक्सलवाद ही था। उन्होंने बताया कि बस्तर जैसे विशाल क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए करीब 200 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए,जिनमें सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान तैनात रहे। इनमें से करीब 70 कैंपों को अब 'वीर शहीद गुण्डाधुर सेवा डेरा' में बदला जा रहा है। इन सेवा डेरों में बैंकिंग सुविधा, आधार केंद्र,कॉमन सर्विस सेंटर, स्वास्थ्य सेवाएं,प्राथमिक स्कूल और सरकारी योजनाओं की सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

बस्तर में बनेगा बड़ा डेयरी नेटवर्क

उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से विकास से वंचित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। महिलाओं को सिलाई मशीन प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें विकास की भागीदारी से जोड़ा जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। बस्तर में हर आदिवासी महिला को पशुपालन से जोड़ने की योजना है। सरकार महिलाओं को गाय और भैंस उपलब्ध कराएगी। 6 महीने में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क बनेगा।

अब तेजी से होगा बस्तर का विकास

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा, नक्सलवाद के कारण पूरा क्षेत्र विकास से कोसो दूर रह गया था। रोजगार की दूर-दूर तक नामोनिशान नहीं था। न गांव में बिजली पहुंची न पानी पहुंचा। अब सारी व्यवस्था सेवा डेरा के माध्यम से पूरे बस्तर में होगी। हमारे जवानों की साहस, बलिदान के कारण बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है। अब तेजी से बस्तर का विकास होगा। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं।

बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जगदलपुर में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बैठक में राज्यों के विकास के साथ-साथ गंभीर सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पर कड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में चारों राज्यों में अपराध नियंत्रण, विशेषकर महिलाओं के उत्पीड़न और रेप जैसे मामलों पर जल्द फैसले लेने पर चर्चा की गई।

जगदपुर में खुलेगा 240 बिस्तर वाला हॉस्पिटल

अमित शाह ने कहा, हमने 20 हजार 557 करोड़ की लागत से 12 हजार 211 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13 हजार मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है, जिसमें से 5 हजार मोबाइल टावर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली है। 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 800 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य स्कूल, 46 आईटीआई, 49 स्कील डेवलपमेंट सेंटर बस्तर में खुल चुके हैं। युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। 240 बिस्तर वाला हॉस्पिटल जगदपुर में खुलेगा, जिसका भूमिपूजन कल किया गया। अब बस्तरवासियों को भय से जीने की जरूरत नहीं है। विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। अमित शाह ने कहा,प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। खेलों से जोड़ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी बार आयोजि बस्तर ओलंपित में 3 लाख 64 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी भाग लिया था।

सुरक्षा से विकास और विकास से समृद्धि तक पहुंचना ही असली नक्सलमुक्ति

अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक वैज्ञानिक रोडमैप तैयार किया है। सुरक्षा से विकास और विकास से समृद्धि तक पहुंचना ही असली नक्सल मुक्ति है। उन्होंने कहा कि हिंसा से कभी विकास संभव नहीं होता। पहले नक्सली स्कूल और अस्पताल तोड़ देते थे, इसलिए विकास रुक जाता था, लेकिन अब 'सेवा डेरा' मॉडल के जरिए गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहुंचाया जाएगा। गृहमंत्री ने बस्तर की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब बस्तर में नया सवेरा आ चुका है।

जांजगीर-चांपा के हसदेव नदी में रेत खदान का टेंडर निरस्त

हाईकोर्ट बोला...बिना फाइनल सर्वे रिपोर्ट के नहीं हो सकती नीलामी, ग्राम-पंचायत की याचिका पर फैसला

बिलासपुर,19 मई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रेत खदानों की नीलामी को लेकर अहम फैसले में जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव नदीं पर रेत खुदाई का टेंडर निरस्त कर दिया है। ग्राम पंचायत हथनेवरा में रेत खुदाई की अनुमति पर डिवीजन बेंच ने कहा कि, बिना फाइनल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी डीएसआर के रेत खदानों की नीलामी नहीं की जा सकती। सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर देना काफी नहीं है, कानूनन इस पर जनता से आपत्तियां मांगना और फिर कलेक्टर से मंजूर कराना जरूरी है। दरअसल, जांजगीर-चांपा जिले में प्रशासन ने बगैर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खुदाई के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसमें पांच साल पुरानी रिपोर्ट को आधार बनाया गया। इसके तहत 30 मार्च 2026 को रेत नीलामी के टेंडर जारी कर दिया गया और बोली लगाने वाले ठेकेदार को फाइनल कर दिया गया।

टेंडर की प्रक्रिया को पंचायत ने दी चुनौती : ग्राम पंचायत हथनेवरा के सरपंच ने टेंडर की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें 30 मार्च 2026 को जारी रेत नीलामी के टेंडर को निरस्त करने की मांग की गई। पंचायत का कहना था कि जिले में कोई वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मौजूद नहीं है। पुरानी रिपोर्ट की 5 साल की अवधि खत्म हो चुकी है, इसलिए बिना नई मंजूर रिपोर्ट के टेंडर जारी करना गलत है।

राज्य शासन का जवाब-रोक लगाने से राजस्व का नुकसान : वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि, साल 2025 की रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी, इसे 27 नवंबर 2025 को इंटरनेट पर भी डाला गया था। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सफल बोली लगाने वालों के नाम तय हो चुके हैं। ऐसे में अब रोक लगाने से सरकारी राजस्व का नुकसान होगा। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पाया कि सरकार ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, वह सिर्फ एक ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, उसे सक्षम अधिकारी ने अंतिम रूप से मंजूर नहीं किया था।

दोबारा टेंडर और अवैध खुदाई पर कार्रवाई की छूट

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि, बिना फाइनल डीएसआर के रेत खनन की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने इस आधार पर हथनेवरा में रेत खनन का टेंडर रद्द कर दिया है। हालांकि, राज्य सरकार को छूट दी है कि वह नियम के मुताबिक नई रिपोर्ट मंजूर कराकर दोबारा टेंडर जारी कर सकती है। इसके साथ ही इलाके में अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी प्रशासन को पूरी आजादी दी गई है।

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को नहीं मिली राहत...हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

बलौदा बाजार,19 मई 2026। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी,जिसे खारिज कर दिया गया। बता दें कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने बलौदा बाजार आगजनी कांड में संलिप्तता पाये जाने के बाद अलग-अलग मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था,जिसके बाद अमित बघेल ने जमानत याचिका लगाई थी। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे,जिसके बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की। वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया। जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया,जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया।

इस हिंसक घटना में सरकारी संपत्तियों को 12.53 करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचा था। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया था।

बढ़ते नशे के कारोबार पर सख्ती

रायपुर,बिलासपुर और महासमुंद में एनडीपीएस कोर्ट का गठन,21 पदों पर होगी भर्ती

रायपुर,19 मई 2026। प्रदेश में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की बढ़ती संख्या और लंबित मामलों के तेजी से निराकरण के उद्देश्य से राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने रायपुर,बिलासपुर और महासमुंद जिले के सरायपाली में एक्सक्लूसिव स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट गठित करने की अधिसूचना जारी की है। उच्च न्यायालय की सहमति और एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 36(2) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार ये अदालतें केवल एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। इससे ड्रग तस्करी, मादक पदार्थों की सप्लाई और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे का रास्ता साफ होगा। राज्य शासन ने रायपुर में एक्सक्लूसिव एनडीपीएस कोर्ट की जिम्मेदारी दसवीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मृति किरण थवाइट को सौंपी है। बिलासपुर में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मृति किरण त्रिपाठी को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के लिए प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल को विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार इन अदालतों का अधिकार क्षेत्र संबंधित सिविल जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा तय कार्य विभाजन के अनुसार रहेगा। तीनों न्यायालय 11 मई 2026 की सुबह से प्रभावी माने गए हैं। नई अदालतों के संचालन के लिए राज्य शासन ने कुल 21 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 3 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, 3 स्टेनोग्राफर, 3 रीडर ग्रेड-1, 3 एक्जीक्यूशन क्लर्क, 3 डिपोजिशन राइटर, 3 प्रोसेस राइटर और 3 भृत्य के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए वित्त विभाग ने आकस्मिकता निधि से प्रतीकात्मक 100 रुपये के अग्रिम व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। बाद में इसकी प्रतिपूर्ति वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में की जाएगी।

महिला तस्करों का पर्दाफाश...कपड़ों की गठरियों में छिपाकर ला रहीं थी 53 लाख रुपये के गांजा की खेप

बिलासपुर,19 मई 2026। 19 मई 20267 छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पुलिस ने रेलवे स्टेशन से दो इलेक्ट्रिक ऑटो में 90 किलो गांजा ले जा रही 8 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। महिलाएं ट्रेन के जरिए ओडिशा से कपड़ों की गठरियों के बीच गांजा छिपाकर लाई थीं। एसीसी और सरकंडा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। जीआरपी ने महाराष्ट्र से 14 किलो गांजा लेकर आए 3 तस्करों को पकड़ा। सरकंडा पुलिस और जीआरपी महाराष्ट्र कार्रवाई में 53.80 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। एसीसी की टीम चाकूबाजी के आरोपियों की तलाश में निकली थी। इसी दौरान करीब 3 बजे सूचना मिली, रेलवे स्टेशन की ओर से दो इलेक्ट्रिक ऑटो सीपत रोड की तरफ आ रहे हैं। इनमें कुछ महिलाएं बोरियों और कपड़ों के गट्ठरों के बीच बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर ले जा रही थीं। सूचना मिलते ही मोपका चौकी पुलिस ने बिलासपुर-सीपत रोड पर स्थित सीमेंट कंपनी के पास घेराबंदी कर दोनों ऑटो (CG 10 BS 7574 और CG 10 CC 3813) को रोक लिया।

कपड़ों की गठरियों के बीच रखा था गांजा : ऑटो में 8 महिलाएं और कुछ बच्चे सवार थे। तलाशी लेने पर प्लास्टिक की 8 बोरियों और कपड़ों के गट्ठों के भीतर खाकी टेप से लिपटे गांजे के 86 पैकेट मिले। हर पैकेट करीब एक किलो का था। तौल कराने पर कुल 90 किलो गांजा बरामद मिला। इसके बाद पुलिस ने सभी महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस का दावा है कि 90 किलो गांजा, दो इलेक्ट्रिक ऑटो और अन्य सामान समेत कुल 46 लाख 75 हजार रुपए का माल जब्त किया गया है। सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया, सूचना मिली थी कि मटियारी गांव की कई महिलाएं कुछ दिनों से ओडिशा गई हुई हैं। जब इस बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि महिलाएं कमाने-खाने के लिए गई थीं। हालांकि पुलिस को शक हुआ कि वे गांजा की खेप लेने गई हो सकती हैं।

रायगढ़ में बूंदाबांदी,दुर्ग-भिलाई में आंधी-तूफान...

गरियाबंद-धमतरी समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट

रायपुर,19 मई 2026। रायगढ़ में शाम होते ही तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। सुबह से तेज धूप और उमस के कारण लोग काफी परेशान रहे। वहीं दुर्ग-भिलाई में भी आंधी-तूफान का असर देखने को मिला। राजधानी रायपुर में भी शाम होते-होते आसमान में बादल छा गए और मौसम सुहाना हो गया। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। गरियाबंद, धमतरी, बस्तर और कोंडागांव जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हल्की बारिश से तापमान में कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। अगले चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को और ज्यादा झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में बिलासपुर प्रदेश में सबसे गर्म रहा,जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

CSMCL ओवरटाइम घोटाले में अनवर समेत 12 आरोपी...182.98 करोड़ की गड़बड़ी,मैनपावर कंपनियों से ढेबर तक पहुंचती थी मोटी रकम,चार्जशीट पेश

रायपुर,19 मई 2026। छत्तीसगढ़ के CSMCL ओवरटाइम भुगतान घोटाला मामले में ACB-EOW ने पहला चालान पेश किया। इस चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें कारोबारी अनवर ढेबर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, तिजऊराम निर्मलकर, अभिषेक सिंह, नीरज कुमार चौधरी, अजय लोहिया, अजीत नरबले, अमित प्रभाकर सालुंके, अमित मित्तल, एन. उदय राव, राजीव द्विवेदी और संजीव जैन के नाम हैं। वहीं, इस मामले में पहले से गिरफ्तार 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद विशेष न्यायालय ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ACB-EOW की जांच में खुलासा हुआ कि साल 2019-20 से 2023-24 के बीच कर्मचारियों के नाम पर ओवरटाइम, बोनस, एक्सट्रा वर्क डे भुगतान और सर्विस चार्ज के रूप में लगभग 182.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम का पैसा मिलना था। लेकिन फर्जी बिल, बढ़े हुए भुगतान और अवैध कमीशन व्यवस्था के जरिए घोटाले की रकम को अधिकारियों, सिंडिकेट और संबंधित कंपनियों के पास गई। जांच में सुमित फैसिलिटीज, प्राइमवन वर्कफोर्स, ए-टू-जेड इंफ्रासर्विसेज, अलर्ट कमांडोज और ईगल हंटर सॉल्यूशंस जैसी मैनपावर एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच इन कंपनियों को कर्मचारियों के नाम पर बड़े पैमाने पर अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें ओवरटाइम के नाम पर लगभग 101.20 करोड़ रुपए, बोनस भुगतान के रूप में 12.21 करोड़ रुपए, 4 अतिरिक्त कार्यदिवसों के भुगतान के तौर पर 54.46 करोड़ रुपए और सर्विस चार्ज के रूप में करीब 15.11 करोड़ रुपए शामिल हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)